खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-01) / अंक-46 बुधवार 8 मार्च, 2017 / 17 फाल्गुन, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-01) में अंक 44 से अंक 48 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (1) बुधवार, 8 मार्च, 2017/17 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-46

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पंकज पुष्कर
3. श्री पवन कुमार शर्मा
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेंद्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविंद
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल
19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री राजेश ऋषि

21. श्री महेंद्र यादव
22. कर्नल देवेंद्र सहरावत
23. सुश्री भावना गौड़
24. श्री सुरेंद्र सिंह
25. श्री विजेंद्र गर्ग
26. श्री प्रवीण कुमार
27. श्री मदन लाल
28. श्री सोमनाथ भारती
29. श्रीमती प्रमिला टोकस
30. श्री नरेश यादव
31. श्री करतार सिंह तंवर
32. श्री प्रकाश
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
36. श्री नारायण दत्त शर्मा
37. श्री अमानतुल्लाह खान
38. श्री राजू धिंगान
39. श्री मनोज कुमार
40. श्री नितिन त्यागी
41. श्री एस. के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्री राजेंद्र पाल गौतम
44. श्रीमती सरिता सिंह
45. मो. इशराक
46. श्री श्रीदत्त शर्मा
47. चौ. फतेह सिंह
48. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-05 बुधवार, 08 मार्च, 2017/17 फाल्गुन 1938 (शक) अंक-46

फाइनल/18415

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा हम सब जानते हैं कि आज विश्व महिला दिवस है। सदन के सभी सदस्यों, विशेषकर महिला सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:' की भावना को ध्यान में रखते हुए नारी का सम्मान करना और उनके हितों की रक्षा करना हमारी पुरानी संस्कृति है। नारी त्याग की मूर्ति है। वह अपने त्याग और परिश्रम के बलबूते पर समाज के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। किसी एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, खेल, साहित्य, उद्योग, सेना, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने आकाश की उड़ान भरी है, सागर में गोता लगाया है, सत्ता संभाली है और लड़ाई जीती है। आधुनिक नारी की गति तेज है, कदम आत्मविश्वास से भरपूर और खुली मानसिकता तथा स्वतंत्र विचारों के साथ वह प्रगति पथ पर अग्रसर है।

एक तरफ तो यह स्थिति बहुत उत्साहजनक है किंतु दूसरी तरफ आज भी लाखों-करोड़ों महिलाएं गरीबी और शोषण का शिकार है। आधी दुनिया का यह पूरा सच है। उनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल कानून बनाने से पूरे अधिकार नहीं मिलते तथा केवल साधनों की उपलब्धि से ही सुधार नहीं होता। इसके लिए समाज की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन लाना जरूरी है। यह केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए जन-जागरूकता आवश्यक है। व्यावहारिक रूप से कानूनी प्रावधानों की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। महिला अधिकारों का सीधा संबंध जीने के अधिकार से है। तमाम बााधाओं के बावजूद विरोध, तिरस्कार और शोषण को नकारते हुए नारी शक्ति जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए यह लगता है कि 21वीं सदी, महिलाओं की सदी के नाम से जानी जायेगी। महिला दिवस का आयोजन करना तब तक सार्थक नहीं हो सकता, जब तक महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन न लाया जाये। इस संदर्भ में मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं :

कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

अभी कुछ क्षणों में बजट पेश होगा। महिला सशक्तीकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे आशा है कि आज के बजट में वे महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ जरूर लेकर आए होंगे। अंत में, आप सबको एक बार फिर महिला दिवस की शुभकामनाएं।

अब माननीय उप-मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वर्ष 2017-18 का बजट भाषण पढ़ेंगे।

वार्षिक बजट 2017-18 का प्रस्तुतीकरण

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसौदिया; : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि मैं लगातार तीसरी बार इस सम्मानित सदन में बजट पेश कर रहा हूं। हर बार, पहले दो बार की तरह, हर बार मैंने बजट तैयार करते वक्त, बजट की तैयारी के वक्त ईश्वर से यही दुआ मांगी है कि :

एक रात को आसमां का निजाम मेरे नाम कर दे,
मैं सारे तारे उठाकर गरीबों में बांट दूं।

अध्यक्ष जी, अपने बजट वक्तव्य में, मैं दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का सदुपयोग करने की दिशा में सरकार की योजनाओं पर बात रखूंगा। दिल्ली की जनता के पैसे का, जनता के लिए इस्तेमाल करते हुए, आने वाले वित्त वर्ष में सरकार के विजन और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करूंगा। साथ ही विगत दो वर्षों में शिक्षा स्वास्थ्य बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा का संक्षिप्त विवरण भी रखना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जा रहे इस बजट की दो बेहद खास बातों का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा।

पहली खास बात तो यह है कि इस बजट को हमने प्लान और नॉन प्लान जैसे परंपरागत ढांचों से परंपरागत सांचों से निकाल कर तैयार किया है। मैंने पिछली बार भी अपने बजट वक्तव्य में इसका जिक्र किया था कि प्लान और नॉन प्लान खर्च आम आदमी की समझ से परे की बात है। उसके लिए तीसरा बजट ही सरकार का खर्च है। तो इस बार का बजट महज कैपिटल

और रेवेन्यू दो हिस्सों में हमने बांटा है। यानि आम लोग अब आसानी से समझ सकेंगे कि जो योजनाएं और प्रोजेक्ट सरकार उनके लिए ला रही है, उनके शुरू होने पर कितना खर्च होगा और उन्हें आगे चलाने पर खर्च कितना होगा। ये हमने पहल की है इस बजट में। ये पहली बात है कि नॉन प्लान और प्लान इसमें खत्म कर दिये हैं। सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू में इस बजट को समझा जा सकेगा।

दूसरी खास बात यह है कि इस वर्ष से हम आउट कम बजट प्रस्तुत करेंगे। ये दिल्ली का और देश का, किसी भी राज्य का पहला आउट कम बजट है। बजट में एकाउंटेबिल्टी की, बजट के आउट पुट की हम हमेशा बात करते रहे हैं, सुनते आए हैं, लेकिन आउट कम बजट उसके आगे की अवधारणा है।

देश में पहली बार किसी राज्य के बजट में अपनाई जा रही है। इसका विस्तृत और पूर्ण ठीक से विवरण मूं आगे रखूंगा लेकिन फिलहाल क्योंकि दो अलग बातों पर मैं जिक्र कर रहा हूं और आउट कम बजट की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए एक मोहल्ला क्लीनिक बनाने में हम 20 लाख रूपये खर्च करते हैं तो नार्मली बजट के आउट पुट में हम ये देखते हैं कि मोहल्ला क्लीनिक की बिल्डिंग बनी या नहीं बनी। हम बस ये देखते हैं। ये बजट आउट पुट है, ये बजट की एकाउंटेबिल्टी है। लेकिन बजट आउट कम है। हम अब ये बात भी शामिल कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये उसका आउट कम होगा और आउट कम एचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर तीन महीने पर इसका

आंकलन होगा। इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। इसकी मॉनिटरिंग हर तीन महीने में की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में, जैसा मैंने कहा कि तीसरी बार दिल्ली सरकार का पूर्ण बजट इस सदन के समक्ष मुझे रखने का मौका मिल रहा है। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी सरकार का मूल कार्य है लोगों को आसानी से जीने के लिए अवसर और वातावरण प्रदान करकना। ऐसे अवसर और वातावरण बनाना ताकि लोग स्वस्थ रहते हुए बेहतरीन शिक्षा हासिल करके समाज में उत्पादन की अथवा सेवा की अपनी भूमिका निभा सके और अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था बहुत गरिमा पूर्ण तरीके से कर सकें। ये महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार में बैठकर लोग अपने आप को व्यवस्था का, सत्ता का, देश का मालिक समझने लगते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी सरकार से क्या चाहता है? आम आदमी तो बस इतना चाहता है कि :

मैं भी अपनी किस्मत लिख सकूं अपने हाथ से,
मेरे भी सफे पर छोड़ दो थोड़ा सा हाशिया।

आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी पूरी कहानी आप लिख दो। वो तो चाहता है थोड़ा सा हाशिया छोड़कर उस हाशिये का ध्यान रखो बाकी तो मैं अपनी किस्मत लिख लूंगा। मुझे खुशी है कि पिछले दो बजट के दौरान हमने इस दिशा में जो विजन सदन के समक्ष रखा, उसके परिणाम केवल दो वर्ष में ही सामने आने लगे हैं और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के काम के प्रति लोगों की उत्सुकता बनी है और लगातार बढ़ रही है। इस रह के कुछ काम, उनका भी उल्लेख करूंगा। एक ऐतिहासिक

निर्णय करते हुए हमारी सरकार ने हाल ही में अर्द्धकुशल, अकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। अकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। अकुशल मजदूर को अब 9724/-रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 13350 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे। अर्द्धकुशल श्रमिकों को 10764/- रू. प्रतिमाह की जगह 14698/-रू. और कुशल श्रमिकों को 11830/- रूपये की जगह 1616822-रूपये प्रतिमाह मिलेंगे। ये देश में पहला अवसर है जब न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया।

इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन में सहयोग के लिए कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में एक हजार रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की है। विकलांग जनों और विधवाओं महिलाओं की पेंशन राशि भी 1500/- रूपये से बढ़ाकर 2500/- प्रतिमाह की गई। एक नए और प्रायोगिक प्रयोग के रूप में हमारी सरकार ने बेघरों के लिए 10 रेन बसेरों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किये हैं। इन स्किल डवलपमेंट कोर्स में जो बेघर लोग है जो हमारे यहां रात बिताने भर के लिए आते हैं और दिन में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, उनको हम ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिलाई, खाना पकाना, सौंदर्य प्रसाधन सेवाएं, प्लम्बर आदि का जो काम वो करते हैं, उसके काम में हम उनको औपचारिक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है। प्रत्येक रैन बसेरे में 25 बेघरों के एक बैच को प्रशिक्षित किया जा रहा है और 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद इसका विस्तार बाकी रैन बसेरों में भी किया जाएगा। अभी 10 से शुरू कर रहे हैं। समूचे शहर में करीब 266 रैन बसेरे हैं जिनमें 21724

बेघरों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। इस तरह गरीब और बेघर व्यक्ति गरिमापूर्ण अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। सरकार ने रैन बसेरों में मोहल्ला क्लीनिकों केज रिए चिकित्सा देख-रेख ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्राईवेट स्कूल में निर्धारित 25 फीसदी कोटे पर दाखिला देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हमने हर संभव उपाय किये हैं। जिसके लिए दाखिला प्रक्रिया को ऑन लाईन कर दिया गया है। इसके पहले जो ईडब्ल्यूएस के दाखिले होते थे, वो सिफारिश पर होते थे या किसी परेंट का कहीं जुगाड़ हो गया, किसी ने सिफारिश लगा दी; नेता ने, अफसर ने सिफारिश लगा दी, किसी जान पहचान वाले ने सिफारिश लगा दी। हमने ऑन लाईन कर दिया है। अब मेरी सिफारिश पर भी शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्य मंत्री या वित्त मुख्य मंत्री या किसी भी सिफारिश पर भी किसी प्राईवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन नहीं हो सकता, ये हमारी गारंटी है। सिफारिश राज खत्म करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने प्राईवेट स्कूल्स के फीस के ढांचे को रेगुलेट करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इन स्कूलों के खातों की लेखा परीक्षा कराई और इसका ऐतिहासिक नतीजा ये निकला कि कई स्कूलों में बढ़ी हुई फीस वापिस ले ली और वसूल की गई अधिक राशि अभिभावकों को रिफंड करना शुरू किया। ये पहली बार देश में हुआ है कि प्राईवेट स्कूल्स, जो हमेशा ये माने जाते हैं कि फीस इनकी बढ़ती चली जाती है। न सिर्फ उनकी फीस बढ़ने से रोकी गई, बल्कि पेरेंटस को, जिनसे बढ़ी हुई फीस ले ली गई थी, बहुत मामलों में उनसे फीस वापिस ली है।

इसी तरह हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के तहत सरकारी विद्यालयों में काम कर हरे गेस्ट टीचर्स यानि अतिथि शिक्षको के वेतन में

ऐतिहासिक वृद्धि की है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को 700 से 900 रूपये प्रतिदिन कार्य की दर से 17 से 21 हजार रूपये के बीच हर महीने मिलता था। लेकिन इस माह से उन्हें 1000 से 145/- रूपये कार्य दिवस की दर से एक माह में 25 सामान्य कार्य दिवस के हिसाब से मिलेगा जिसमें 25000/- रूपये से 36000/- रूपये प्रतिमाह मिलेगा, 17 से 21 मिलता था उनको अभी तक। अब 25 से 36 हजार रूपये के बीच मिलेगा। इससे अध्यापक शिक्षा के प्रति संकल्पबद्ध और प्रेरित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। दिल्ली में हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करना, हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन चिकित्सा की व्यवस्था करना, हमारी सरकार ने पिछले दो वर्ष में अपने लक्ष्यों में रखा था। सरकार स्कूलों में नए कमरे बनवाना, हर स्कूल में पेयजल, साफ-सुथरे टॉयलेटस की व्यवस्था करने के लक्ष्य में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार लाते हुए अपने प्राधानाचार्य को हमने कैम्ब्रीज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया है। मैंटर टीचर को सिंगापुर भेजा जा रहा है। आईआईटी और आईआईएम जेसी देशी नामी संस्थाएं, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के हमारी मदद कर रही हैं। शिक्षा के लिए समर्पित प्रथम सांझा, क्रिएटनेट, जोड़ो ज्ञान जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी विकसित करने पर काम किया और एक लाख से अधिक ऐसे बच्चे जो अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ने में भी अक्षम थे, उनको हमने अपनी पाठयपुस्क पढ़ने की योग्यता विकसित करने में मदद करने में सफलता हासिल की है।

हमने बैचलर स्तर तक की पढ़ाई के लिए नौ नए वोकेशनल कॉलेज शुरू किये हैं जिससे हायर एजूकेशन में 2700 सीटें बढ़ गई हैं। हमारा वर्ल्ड क्या

स्किल सेंटर हजारों बच्चों को देश के सबसे बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से, हायर एजूकेशन से वंचित न रह सके, इसके लिए 10 लाख रूपये तक के लोन की गारंटी हमारी सरकार ले रही है। (12.20)

इसी तरह, दिल्ली के हर नागरिक के मन में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा जगाने में हमारा 'मोहल्ला क्लीनिक्स' एक सफल प्रयोग रहा है, जहां महज 110 मोहल्ला क्लीनिक्स में 26 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। अस्पतालों में 10 हजार नए बेड्स का इंतजाम होने से लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ऐसे नये प्रयोग किए हैं, इसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। जिसके तहत दिल्ली में पहले से मौजूद प्राइवेट क्लीनिक्स, टेस्ट सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए उनको लिंक कर दिया है। इससे टेस्ट या ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को कई-कई महीने और कई बार तो साल भर की डेट मिलती थी, अब उन्हें कुछ दिनों से टेस्ट या ऑपरेशन की डेट मिल जाती है। ये बहुत बड़ा सकून है। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी के लिए, दिल्ली की सरकार के काम से कि वो सरकारी अस्पताल में जाता था तो उसको डेट पे डेट, ऐसे मिलती थी जैसे मुकद्मे की तारीख के लिए आ रहा हो। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के लिए या ऑपरेशन के लिए जो व्यवस्था कर दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। उसे लिंक कर दिया है, उसका फायदा ये हुआ है कि आम आदमी अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गवर्मेंट हॉस्पिटल में जा सकता है और जाता है, जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति लोगों के अंदर भरोसा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव कम करता है और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दो साल के अंदर लोगों के अंदर इस असुरक्षा के भाव को काफी हद तक कम किया है। लोगों के अंदर जो डर रहता है, हॉस्पिटल और स्कूल की व्यवस्था को लेकर उसको डर हमने कम किया है आज।

इसी तरह बिजली के दामों में 50 परसेंट की कमी, 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी की सुविधा से लोगों को हर महीने आर्थिक लाभ पहुंचा है जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने में हमें काफी कामयाबी मिली है। साथ ही, लोगों में बिजली और पानी को सहज कर रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। आज दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है और अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की स्वच्छता के स्तर को हम इस स्तर तक ले जा रहे हैं कि लोग खुद अपने नल खोलकर सीधे दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से टोंटी खोलकर पानी पी सकते हैं, ये हमने व्यवस्था की है। इसकी ऐतिहासिक शुरूआत हाल में दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 11 जोन से की गई। इन 11 जोन्स में आने वाली कालोनियों के घरों में नल से सप्लाई होने वाले पानी की स्वच्छता की गारंटी दिल्ली जल बोर्ड ने ली है। अधधक्ष महोदय, धीरे-धीरे यही गारंटी पूरी दिल्ली में हर एक घर की, हर एक टोंटी में लेने की दिल्ली जल बोर्ड की योजना है, दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग समर्थन है।

शहर की गति बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया गया है। इससे पश्चिमी दिल्ली से वजीराबाद तक पहुंचने में लगने वाला समय अब काफी कम होग या है। बारापुला फेस-3 और मैट्रो फेस-3 का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। मैट्रो फेज-4 लोनी बॉर्डर से वजीराबाद

तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो जाएगा।

वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिनके पास लाभार्थियों का अलग-अलग डेटाबेस है। एक हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय, अनेक पहल की हैं कि सबका अपना-अपना डेटा बेस है। सारे डिपार्टमेंटस अपना अलग अलग डेटा बेस रखते है। उनका कोई आपस में लिंक नहीं है। हमारी सरकार ने आधार, आयकर पेन, मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि के मौजूदा डेटाबेस की एकीकृत करके एक कॉमन डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया है। इस कॉमन डेटाबेस की सीडिंग जितनी भी हम पब्लिक सर्विस, वेलफेयर सर्विस, जिन सेवाओं के वितरण में होता है, उसे इसको सीड करने का प्लान बना रहे हैं। इससे हर एक डिपार्टमेंट का डेटाबेस आपस में लिंक हो जाएगा इससे लाभार्थियों की, जो भी बेनिफिसरीज हैं, हमारी स्कीम्स की, उनकी सही पहचान हो सकेगी और सेवाओं के वितरण में समय और लागत में भी कमी आएी। इस विशिष्ट डाटोबेस सृजित आंकड़ों का इस्तेमालन ये वेलफेयर स्कीम्स बनाने में, नये प्रोजेक्ट्स शुरू करने में भी किया जाएगा, जिससे डुप्लीकेसी से बचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजों का जिक्र मैंने इस लिए किया ताकि आगामी वित्त वर्ष के बजट को भी हम उसी अवधारणा के आधार पे समझ सकें जिसके लिए मैंने जिक्र किया था कि सरकार का काम है लोगों की आसानी से जीवन जीने में सहयोग कर सकें। लोग अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं। सरकार का काम है कि हम उनके आसानी से जिंदगी जीने में सहयोग कर सकें।

अब थोड़ा सा समय दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर लेना चाहूंगा और दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य की जब बात मैं करूं तो अर्थव्यवस्था की दिल्ली

की बात होगी। एक छोटा सा कमैंट है, यहां मैं जरूर करूंगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई सिक्के उछाल के नहीं चलती या टॉस उछाल दीजिए। चित्त आ जाए तो ऐसा, पट आ जाए तो ऐसा। अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेन स्टार्मिंग करनी पड़ती है, डेटा समझना पड़ता है। लोगों की जिंदगी की जरूरतें समझनी पड़ती हैं और हमने बड़े मुश्किल से ये दौर से निकला अर्थव्यवस्था को भी जिस वक्त दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था उस समय भी नहीं डूबी। लेकिन जब टॉस छाल के अर्थव्यवस्थाओं को चलाने का चलन हमारे देश में आने लगा तो उसका नुकसान मैं आपको बताऊंगा। किसी शायर ने भी कहा है :

सब फैसले होते नहीं सिक्के के उछाल के।
ये जिंदा कौम के मसले हैं, जरा देखभाल के।।

लेकिन हमारे देश में अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले दिनों में देखा कि बकायदा सिक्के उछालकर हेड या टैल देखकर डिसिजन लेने की अर्थव्यवस्था में बड़े-बड़े डिसिजन लेने की परंपरा हमने देखी। एक बड़ा वो हमने देखा और उसका नाम हमने रखा नोट बंदी। मुझे नहीं बता कि किसी ने स्टडी की है या नहीं की, मुझे नहीं पता कि लोगों की जिंदगी, जिंदा कौम के मसलों को किसी ने समझा की नहीं समझा। बस टॉस उछाला, किसी कमरे में बैठके हेड या गया तो नोट बंदी कर देंगे, टेल आ गया तो नहीं करेंगे। और मुझे लगता है उसी तरह से ये फैसला किया गया। जिक्र जरूरी है इसका। क्यों? जब नोट बंदी हुई मैं खुद दिल्ली के बाजारों में गया हमारे बहुत सारे साथी गए, मीडिया वाले रेलवे स्टेशन से खड़े हो के रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किसी तरह से नोट बंदी की वजह से जो मजदूर क्षेत्र है देश के, वहां जाने में भी ट्रेनें

लगातार भर के जा रही हैं और आने वाली ट्रेनें खाली आ रही हैं हालात से हो गए थे अध्यक्ष महोदय, कि :

घर में पड़ी तनख्वाह क गड्डी तक किसी काम न आई,
बच्चों के गुल्लक तोड़े, तब जाके घर में सब्जी आई।।

ऐसे हालात दिल्ली में पैदा किए गए देश भर में पैदा हुए लेकिन मैं दिल्ली के वित्तीय मंत्री के रूप में दिल्ली की चिंता इस सदन के रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि लोगों ने बात हमसे कही है, हम लोग व्यापारियों से मिले दिल्ली में जाके, हम लोग आम लोगों से मिले, एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर से मिले जिसने इसलिए सूसाइड कर लिया क्योंकि उसके घर में रखे हुए 5 हजार रूपये किसी काम नहीं आ रहे थे और उसके घर में तो बच्चों के गुल्लक भी नहीं थी। उसके पास इतना ही था कि वो फांसी लगा के सुसाइड कर ले, ऐसे लोगों के भी हम घर गए।

अध्यक्ष महोदय, ये मैं अर्थव्यवस्था की बात करते हुए करना चाहता हूं। दिल्ली की अर्थग्व्यवस्था पिछले साल इन हालात से गुजरी है। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का अपना डायमनिक इकॉनोमिक कल्चर है दिल्ली की एक डायमनिक इकोनॉमिक नोट बंदी के नकारात्मक असर के बावजूद दिल्ली का जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों में 2016-17 में बढ़कर 6,22,385 करोड़ रूपये पहुंचने की संभावना है जो 2015-16 में 5,51,963 करोड़ रूपये था यानि कि इसमें 12.76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। ये दिल्ली का अपना एक इकॉनोमिक्स का डायनमिक्स है। वास्तव में आधार वर्ष 2011-12 के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर 2016-17 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली की जीएसडीपी

में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। मैं यहां रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि पिछले साल ये 1.32 या 1.63 में यहां पे मेरे पास वक्तव्य नोट नहीं है। दिल्ली का जीएसडीपी नीचे गया है, पिछले साल के मुकाबले। हालांकि, उसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी के 7.1 परसेंट जोड़ा है, उससे ऊपर रहा है, रहने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर की जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2011–12 के 3.94 के प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 4.08 हो गया है। हालांकि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43 प्रतिशत है। दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 82.26 प्रतिशत है। उसके बाद माध्यमिक क्षेत्र का योगदान 24.87 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.90 प्रतिशत है। ये आर्थिक परिदृश्य है दिल्ली का जिसको यहां रखना जरूरी है। दिल्ली की, क्योंकि अगले साल का हमारा बजट किस आर्थिक परिदृश्य, किन घटनाओं, विघटनाओं पे आधारित होगा। इसलिए ये जरूरी हैं आंकड़े। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2016–17 में बढ़कर 3,03,073 रूपये होने की संभावना है जो कि 2015–16 में 2,73,618 रूपये थी। इससे पता चलता है कि 15–16 की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 10.76 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015–16 में 94,178 रूपये थी जो 2016–17 में बढ़कर 1,03,818 रूपये की संभावना है जिसमें 10.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी। दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय से करीब दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय स्तर की आय से करीब तीन गुना अधिक है अध्यक्ष महोदय। ये एक डायनमिक समझना जरूरी है कि क्योंकि जब मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं, जब मैं जीएसडी में ग्रोथ की बात कर रहा हूं। लेकिन साथ–साथ पिछले साल की तुलना में जीएसडीपी के दिल्ली

के जीएसडीपी के लो रहने की बात कर रहा हूं तो उस सबमें ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूर्व में क्या थी और वर्तमान में क्या है।

अध्यक्ष महोदय अब मैं 2016-17 जो चालू वित्तीय वर्ष है इसके कुछ संशोधित अनुमान सदन के समक्ष रचाना चाहता हूं। चालू वित्तीय वर्ष का हमारा गैर योजना व्यय बजट में 26 हजार करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया था यहां भी नोटबंदी को देखना बहत जरूरी है। 26 हजार करोड़ रूपये का हमने गैर योजना व्यय अनुमोदित किया था। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्तीय वर्ष में कुल गैर योजना व्यय 24,700 करोड़ रूपये के स्तर तक सीमित रखने में सफल होंगे। ये उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद हासिल होगी कि हमने उत्तरी और पूर्वी नगर निगम को वेतन खर्चों से आंशिक रूप से निपटने के लिए 400 करोड़ रूपये का आकस्मिक ऋण भी हमें उनको देना पड़ा। सरकारी धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से करते हुए ये कामयाबी हासिल हुई है। योजना टॉस उछाल के नहीं हुई है, ये ध्यान रखने की चीज है। ये योजना परिव्यय जो 20,600 करोड़ रूपये प्रस्तावित अनुमोदित किया गया था पिछले वर्ष, उसे दो वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों में घटाकर 16,500 करने का प्रस्ताव है। 2016-17 में 16,500 करोड़ रूपये का संशोधित योजना व्यय 2015-16 के 14935 करोड़ रूपये के योजना व्यय से 10.5 फीसदी अधिक है। चालू वर्ष के लिए हमारा संशोधित अनुमान 41200 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जबकि बजट अनुमान 46600 करोड़ रूपये का था। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 में ख्र्च की गई 35196 करोड़ रूपये की तुलना में 17.1 फीसदी अधिक है। इन सारी चीजों में, मैं फिर से कहूंगा, लक्ष्य बड़े थे, इरादे बहुत बुलंद हैं और जो भी हमने अर्थव्यवस्था की पिछले

साल तस्वीर रखी थी, वो बहुत व्यावहारिक स्तर पर रखी थी। अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज हमें साढ़े चार पांच हजार करोड़ रूपए का अपना प्लान बजट नीचे नहीं लाना पड़ता। अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत पूरक मांगें 688.73 करोड़ रूपये की है। अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुदान करने की विनती करूंगा।

अध्यक्ष जी, मैं आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा करना चाहूंगा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2017-18 के बजट अनुमान योजना और गैर योजना दोनों मदों में नहीं होंगे बल्कि इस पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए हमारी सरकार ने 2017-18 के बजट में दो प्रमुख श्रेणियों, राजस्व और पूंजी इन दोनों फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे संसाधन आबंटित किए हैं। तो ये बजट बुक होती हैं, इसमें इस बार आप रेवेन्यू और नान-रेवेन्यू का हेड नहीं देखेंगे। आप कैपिटल और रेवेन्यू प्लान और नान-प्लान नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू के हेड मिलेंगे। इसी तरह, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस वर्ष का बजट सार्वजनिक खर्च पर पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से नवीनता लिए हुए बजट है। वो है। इस नवीनता का नाम हमने दिया है आउटकम बजट जिसका जिक्र मैंने शुरूआत में ही किया था। यहां मैं थोड़ा सा उस पे और रोशनी डालना चाहूंगा ताकि सभी माननीय सदस्य और माननीय सदस्यों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक ये आउटकम बजट की पूरी कांसेप्ट पहुंच सके। हमारी सरकार का मानना है कि सरकार और नागरिकों के संबंध एक पवित्र कान्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। सरकार और नागरिकों के बीच एक तरह का कान्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है हम सब। ये एक ऐसा करार है कि जो करदाताओं की, उसकी टैक्स की कमाई के बदले में बेहतरीन नतीजे और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसी तरह आउटकम

बजट अब सरकार और उसके विभिन्न विभागों के बीच एक कान्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की तरह होगा, एक करारना में की तरह होगा। विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे, विभाग अपना लक्ष्य तय करके सरकार को बतायेंगे सरकार उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागों को पैसा देगी और हरेक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा की जाएगी, ये अभी तक नहीं होता था। कहीं भी नहीं होता। देश में यहां होना शुरू होगा तो सरकार और डिपार्टमेंट के बीच में एक तरह का कान्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इस आउटकम बजट से आने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे घोषणा करते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार का आउटकम बजट 31 मार्च, 2017 तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बजट सार्वजनिक ख्यर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यहां ये समझना जरूरी है कि यह बजट संबंधी एक अहम सुधार क्यों है परंपरागत बजट और इसमें अंतर क्या है। परंपरागत बजट में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन नोट पर जोर दिया जाता है एलोकेशन्स पर जोर रहता है और काम-काज का आकलन इस तरह से होता है कि आबंटन किया था और उसको खर्च हो गया तो आकलन हो गया उसका। सिर्फ कुछ मामलों में कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप तैयार इंफ्रास्ट्रकचर या सर्विसिज का हम बजट में उल्लेख करते हैं और सरकारी कार्यक्रमों से जिन नतीजों या लोगों को फायदे की उम्मीद है, उनका जिक्र तो बहुत दूर की बात है कि बजट न हो। मिसाल के तोर पर परंपरागत बजट में स्कूल और क्लीनिक के निर्माण के लिए आबंटित ध नराशि का जिक्र तो किया जाता है मगर ये नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को इनसे फायदा मिलने का और कितने समय में कितने लोगों को फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है। बजट बनाने की इस परंपरागत तरीके की दो खामियां

है। अध्यक्ष महोदय, इसमें इस तथ्य को पहले तो नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से आए हुए टैक्स के पैसे की टैक्स की संरक्षक है सरकार का काम महज एक खास अवधि के भीतर पैसा खर्च करना नहीं होना चाहिए। उसको ये भी देखना चाहिए कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जो उम्मीद व अपेक्षा है, वे पूरी की हो। दूसरी बात जो दूसरी खामी इसकी है, वो है कि परंपरागत बजट में जनता के पैसे के खर्च होने की निगरानी का काम सरकार के बाहर से तो छोड़िए, सरकार के अंदर से भी मुश्किल हो जाता है। अब तक बजट को योजनागत हिस्से में ही कार्यक्रमों और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता है जिसको प्लान कहते थे जबकि जो नान-प्लान हिस्सा है उस और जो कि बजट का आधे से ज्यादा होता है, उसकी कोई समीक्षा नहीं होती थी, इसलिए सब कमियों की ओर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक विभाग और एजेंसी ने बहुत जबरदस्त कवायद की है और उसमें सभी कार्यक्रमों और योजनाओं भले ही वो कैपिटल हो या रेवेन्यू की हो, उनका जायजा ठोस परिणामों को ध्यान में रख के लिया गया यानि कि कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे या उपलब्ध करायी गई सेवाओं और उसके नतीजे क्या होंगे, इसको देखकर ही ये विचार किया गया कि दिल्लीवासियों को इस खर्च से अल्पावधि में क्या फायदा होने जा रहा है, दीर्घावधि में क्या फायदा होने जा रहा है, उन योजनाओं के निष्पादन और परिणामों के संकेतकों की एक इंडीकेटर्स की लिस्ट तैयार की गई है, एक सेट तैयार किया गया है जिसके आधार पर नतीजों का मापना उनको इवेल्युएट किया जा सकेगा। 2017-18 को आधार वर्ष मानकर, क्योंकि पहली बार हो रहा है इससे पहले तो कोई देश या माना नहीं जा सकता। 2016-17 को आधार वर्ष मानकर बुनियादी मापदंड तय कर दिए गए हैं और

2017-18 के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि तय किए गए संकेतक विशिष्ट हों, मापन योग्य हों और इसी तरह संस्था और कार्यक्रमों जैसे अस्पताल, कालेज, पेंशन आदि से जो तुलना करने योग्य हो। इसको मैं कुछ उदाहरण से भी समझाऊंगा जेसे किसी अस्तपाल में हमने 10 करोड़ रूपए का खर्च करके मान लीजिए एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं, बहुत कॉमन उदाहरण है; किसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रूपये खर्च करके एक स्केनिंग मशीन लगाते हैं। अब सरकार के रिकार्ड में अगर 10 करोड़ रूपये खर्च हो गए तो बजट अच्छा मान लिया जाता है। अगर मशीन आ गई, मशीन आकर वहां खड़ी हो गई तो संतुष्टि मान ली जाती है, भले ही खरीदने के बाद से अब तक उस मशीन से एक भी आदमी का टैस्ट नहीं हुआ हो। लेकिन बजट संतुष्ट हो जाता है। आउटकम बजट इससे संतुष्ट नहीं होगा, आउटकल बजट पहले से ही निर्धरित लक्ष्य तय करके चल रहा है कि ये 10 करोड़ रूपये खर्च करके जो मशीन लाओगे, उससे कितने लोगों का टेस्ट होगा? वो टेस्ट जब तक होने शुरू नहीं हो जायेंगे, वो टेस्ट अभी तक अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो बजट होता था, ये सिर्फ एक डाक्युमेंट्स से चलता था जिसको हम डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। इसमें सारा होता था। लेकिन ये किताब संतुष्ट हो जाती है अगर 10 करोड़ रूपये के आगे 10 करोड़ रूपये लिख दिए गए, खर्च हुए नौ करोड़ रूपये लिख दिए गए तो ये किताब संतुष्ट हो जाती है। लेकिन ये दूसरी बुक तैयार कर रहे हैं। ये आउटकम बजट की बुक है, ये संतुष्ट नहीं होगी। ये आपसे पूछेगी, ये हमसे पूछेगी या सरकारी विभाग से पूछेगी कि ये जो 10 करोड़ रूपये खर्च किए गए इसमें कितने लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया? अभी तक कोई टेस्ट क्यों नहीं शुरू हुए? अभी तक उन लोगों का इलाज होना क्यों नहीं शुरू हुआ? ये

आउटकम बजट है। मुझे लगता है कि ये उदाहरण बहुत सामान्य जन का उदाहरण है। लेकिन इस आउटकम बजट की पूरी कांसेप्ट को समझने में मदद करेगा।

इसी तरह मान लीजिए, दूसरा उदाहरण क्योंकि मैंने दो-तीन उदाहरण नोट किए कि मान लीजिए जैसे अभी हम हाल में प्रगति मैदान के पास 54 करोड़ रूपये खर्च करके स्काई-वॉक बना रहे हैं। अब इस बजट में ये स्काई-वॉक बन गया। उसके फोटो छप गए, सब कुछ हो गया, ऑडिट हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जायेंगे। लेकिन इसकी योजना क्या है? लोग नीचे से निकलते हैं, रेड लाइट पार करके निकलते हैं, लोगों को जान पर रिस्क ले के निकलना पड़ता है, समय लगता है, वो सब के सब अगर ऊपर आकर रेड लाइट क्रॉस करने की जगह, भाग कर सड़क पार करने की जगह, भारी ट्रैफिक में सड़क पार करने की जगह ऊपर शिफ्ट हुए कि नहीं हुए। उस स्काई-वॉक का यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे, अगर उसमें खामी है तो ये आउटकम बजट में, हरेक तिमाही में इसका आंकलन होगा। जब ये चीजें हो जाती हैं।

इसी तरह से एजुकेशन में हम लोग 283 करोड़ रूपये खर्च करके जौनापुर में एक विश्वस्तरीय कौशल केंद्र बना रहे हैं 'स्किल डवलपमेंट सेंटर'। सामान्य बजट में राशि खर्च होने की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से संतुष्टि मान ली जाती है लेकिन आउटकम बजट में शिक्षा विभाग को, सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इससे कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली है, उसमें से कितनों को नौकरी मिली है और कितनों ने अपना रोजगार शुरू किया। ये आउटकम बजट था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था, दिल्ली की सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है, इससे आज दिल्ली की सरकार, भारत में पहली जो ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो आउटकम बजट लेके आ रही है।

आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर जो लोग यहां पर आयेंगे, उनके लिए सूचना टैक्नोलॉजी पर आधारित एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है। ये एप्लीकेशन विभागों द्वारा उपलब्ध किए गए रिपोर्ट या आंकड़ों से हरेक तिमाही में सरकार के तमाम वायदों पर नजर रख सकेगी। और कुछ मामलों में तो वह स्वतंत्र सर्वेक्षण के आधार पर भी ऐसा करेंगे हम लोग। हमें आशा है कि इससे भारत में किसी भी सरकार की कार्य निष्पादन के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए मापदंड तैयार होंगे।

मैं दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारियों और योजना विभाग को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खासतौर पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात का भी अहसास है कि इतनी बड़ी कवायकद का यह पहला साल है और पहला साल होने की वजह से इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें लगातार सुधार किया जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इस कवायद से सभी सम्बद्ध पक्षों को भरपूर फायदा होगा। मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी इसका इस्तेमाल अपनी सभी गतिविधियों को लगातार आंकलन के लिए करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि समय पर इसमें सुधार भी होता रहे। क्रियान्वयन के स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को भी इसका फायदा मिलेगा क्योंकि इससे उन्हें सफलताओं के साथ-साथ चुनौतियों को भी परामर्श तरीके से और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करने का शानदार मौका मिल जाएगा। मगर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के सिटीजन्स को होने जा रहा है। पूरी पारदर्शिता होने के कारण वे जान सकेंगे कि उनकी पसीने की कमाई कहां और किस तरह से खर्च की जा रही है और उसका आउटकम क्या है। आउटक्म बजट नागरिकों और उसकी निर्वाचित सरकार के बीच, जैसा मैंने कहा, करार है, उस करार को अंजाम देने वाली एक प्रणाली बन जायेगा

और इस तरह सरकार और उसके विभागों को भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आउटकम बजट की एक लास्ट स्पीच इम्पार्टटैंट है कि ये सिर्फ एक बुक बनाने से नहीं होगा बल्कि हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक आउटकम बजट को अमल में लाने के लिए योजना विभाग में निगरानी और मूल्यांकन ईकाई, मॉनिटरिंग और रिवोल्यूशन यूनिट को मजबूत बना रहे हैं। ये इकाई दिर्ली सरकार के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों और तकनीकों के कारगर इस्तेमाल के लिए पूरा रोड मैप उपलब्ध करायेगी और इससे नीतियों के निर्माण में सुधार आयेगा और सार्वजनिक सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचायी जा सकेंगी। तो ये एक मानिटरिंग और रिवोल्यूशन यूनिट है वो भी बहुत इम्पार्टटेंट हिस्सा होगा इसका। आउटकम बजट को निदशानिर्देश देने के अलावा इससे दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करने, मूल्यांकन कराने और आंकड़ों का विश्लेषण करने यानी डेटा एनालिसिस करने और सरकार के विशाल डेटाबेस का जायजा लेने की इस एक यूनिट से मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2017-18 के बजट अनुमान पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के लिए कुल बजट अनुमान 48000 करोड़ रूपये का प्रस्तावित किया गया है जिसमें 29500 करोड़ रूपये प्रशासनिक व्यय, स्थानीय निकायों का हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज व मूलधन की अदायगी, परिवहन, पानी और बिजली सब्सिडी आदि के लिए है। 48000 करोड़ में से 29500 करोड़ रूपये इस पर है और इंट्रेस्टिंग बात ये है अध्यक्ष महोदय, कि इसमें 4000 करोड़ रूपये, इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 4000 करोड़ रूपये हम प्रिंसिपल एमाउंट और इंट्रेस्ट एमाउंट के रूप में भारत सरकार

को देते आ रहे हैं। जब नगर निगमों को लोन दिया गया तो उसमें से न हमने पिछले दो साल में न प्रिंसिपल एमाउंट काटा है, न इंट्रेस्ट एमाउंट काटा हैं ये फैडरल स्ट्रक्चर एक ताने बाने से चलता है इसलिए हमने किया क्योंकि दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का जब हम हिसाब-किताब लेके बैठते हैं। और ये पता चलता है कि इसमें से 4000 करोड़ रूपये तो भारत सरकार को इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल एमाउंट के रूप में चले जा रहे है। कहां चले जा रहे हैं, इसका जिक्र मैंने यहां पर कई बार किया है कि अगर ईमानदारी से हिस्से देने में आते तो कई हजार करोड़ रुपये तो अभी दिल्ली के लोगों के भारत सरकार पर निकल रहे हैं। उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उसके उलट हमें 48000 करोड़ रूपये में से करीब 40000 करोड़ रूपये हमें प्रिंसिपल एमाउंट और इंटरेस्ट में हमें भारत सरकार को लौटाने पड़ रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हमें भी और काम करने का मौका मिलता। ये, तो 29500 करोड़ रूपये का मैंने बताया। इसी तरह 18500 करोड़ रूपये विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और पूंजी परियोजनाओं जिसे कैपिटल कहते हैं, उससे संबंधि त है। प्रस्तावित 48000 करोड़ रूपये के बजट के लिए धन की व्यवस्था में 38700 करोड़ रूपये कर राजस्व से, 800 करोड़ रूपये गैर कर राजस्व से, 400 करोड़ रूपये पूंजी प्राप्तियों से, 2856 करोड़ रूपये लघु बजट के ऋण से, 1500 करोड़ रूपये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, 413 करोड़ रूपये सामान्य केंद्रीय सहायता से और 325 करोड़ रूपये सेंट्रल फंड्स में डेविडेशन से मतलब शेयर से और 478 करोड़ रूप्ये भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों और बाकी राशि प्रारंभिक शेयर से जुटाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 20917-18 में स्थानीय निकायों को 7571 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रस्तावित करती है जो कुल बजट का

15.8 फीसदी है। हमेशा बात होती नगर निगम को कितना दिया, कितना नहीं दिया। मैंने जिक्र किया कि जितना लोन हमसे पहली सरकारों ने भी दिया हुआ था। जब इस तरह का पैसा देते थे तो लोन भी काटते थे और प्रिंसिपल भी काटते थे। आज इस चेयर पर खड़े होके मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि एक भी साल में पिछले दो साल में एक भी बार नगर निगमों को दिये गये लोन और उनके इंटरेस्ट को नहीं काटा गया है और उसके बावजूद 15.8 फीसदी बजट नगर निगम को दिया जाता है और वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में दिये गये धन 14.9 फीसदी अधिक है। पिछली बार से 14.9 फीसदी ज्यादा दे रहे हैं और इस बार का कुल मिला के देखें तो 15.8 फीसदी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगामें की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमने 2015-16, 2016-17 में निगमों के अनुदानों से बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की। जिसका मैंने जिक्र किया। 2017-18 में स्थानीय निकाहों की वित्तीय सहायता में 3343 करोड़ रूपये कर वसूली में हिस्सेदारी, 1810 करोड़ रूपये स्टाम्प और पंजीकृत शुल्क और एक बारगी पार्किंग के शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित है और 700 करोड़ रूपये उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों का वेज मीन्स के रूप में, अग्रिम रूप में है। शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर अमल करने के लिए हम इस वित्तीय वर्ष में 1718 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करते हैं, नगर निगमों के लिए। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के प्रति कटिबद्ध है। हम नगर निगमों के साथ निरंतर संपर्क बनाके रखे हुए हैं ताकि उन्हें स्वयं के संसाधन बढ़ाने और निरंतर बढ़ते खर्चों पर युक्तियुक्त नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से नगर निगमों से अपील करता हूं कि वो

अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं ताकि नगर प्रबंधन में कोई आर्थिक संकट न आये और इस महान शहर के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े।

अध्यक्ष जी, अब मैं 2017-18 के बजट में प्रस्तावित प्रमुख विकास उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। इन सभी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा सम्माननीय सदन में प्रस्तुत किये गये बजट के दस्तावेज में रखा जा रहा है।

अध्यक्ष जी, सरकार के लिए शिक्षा सबसे अधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हमने पिछले दो साल में नये स्कूल बनवाने, नये क्लास रूम बनवाने, खेलों के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाएं आदि के निर्माण के रूप में व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिल्टीज डेवलप की हैं। इस साल 24 नये स्कूल शुरू हो रहे हैं। 8000 नये कमरों का काम लगभग पूरा हो चुका है जो कि अगर बहुत मोटे तौर पर देखें तो लगभग 200 स्कूल से ज्यादा का इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा 10000 नये कमरे अगले वित्त वर्ष में बनाने का काम हम शुरू कर देंगे। अगर 224 नये स्कूल अभी शुरू हो रहे हैं। 8000 कमरे बन के तैयार हैं। लगभग 10000 और नये बन जायेंगे तो मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय, कि अगले 15-20 साल तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। हमारी कोशिश है कि दूसरी पाली में चलने वाले अधिकतर स्कूलों को जहां तक संभव हो, पहली पाली में ले आयें। ये भी बड़े पैरेंटस की शिकायत रहती है। इन्क्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी हे। इसलिए 700 स्कूल अभी दोनों शिफ्ट में चलते हैं। मैं एक साल 700 स्कूल्स को नहीं, लेकिन धीरे-धीरे जहां तक संभव हो, जहां-जहां संभव होगा, एक-एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में लाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए हमने ये तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वलिटी एजूकेशन पर जोर देने पर ध्यान दिया है।

क्वालिटी एजकेशन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और डाइट को पुनर्गठित करने का फैसला किया है। उसके लिए हमने दिल्ली में दो नये डाईट्स खोलने का भी फैसला किया है। दिल्ली में अभी तक दो डाईट्स की कमी थी। हरेक जिले में एक डाईट होना चाहिए। दोन ये डाईट इस साल से हम दिल्ली में खोलेंगे। सरकार ने 2017-18 में 156 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की कक्षायें शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हमने इस सदन में बार-बार बैठके कहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राईवेट स्कूल जैसा बनायेंगे। उसमें बुनियादी खामी ये थी कि पैरेंट जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाता है अध्यक्ष महोदय, तो वे प्राईवेट स्कूल में जाता है, तो नर्सरी से एडमिशन मिलता है। सरकारी स्कूल में जाता है तो क्लास वन से एडमिशन मिलता है। इसलिए हमने इस बार ढांचे को देखते हुए 156 स्कूलों में नर्सरी की क्लासेज शुरू करने का फैसला किया है ताकि लोगों को प्राईवेट स्कूल के बराबर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के अवसर, उस जैसे माहौल में मिल सके। एक और इम्पार्टटेंट कदम है एजूकेशन में; हमने बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री-स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए उठाया है। सरकार की योजना पूरी दिल्ली में हरेक वर्ग के बच्चों को बेहतरीन प्री-स्कूल लेवल उपलब्ध कराने के लिए अर्ली चाईल्डहुड लर्निंग सेंटर खोलने की है। ये अपने आप में विश्वस्तरीय सेंटर होंगे। जहां दो साल, छठी क्लास से तो बच्चा आता है तो पहली, छठी साल के उम्र से बच्चा आता है तो पहली क्लास में जाता है लेकिन दो साल से

छः साल के बच्चों को आधुनिक और आकर्षक सुविधा उपलब्ध करायी जा सके सीखने की। ये इन प्री–प्राईमरी लर्निंग सेंटर प्री–स्कूल लन्रिंग सेंटर में होगा और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज पर आधारित औपचारिक स्कूली शिक्षा करने से पहले हम उस पर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ऐसे हुए हैं, जिनमें ये बात निकल के आयी है कि अगर बच्चे के दो साल से छः साल के उम्र में लर्निंग एबिलिटीज यानी कि उसकी सीखने की योग्यता पर काम कर लिया जाये तो पहली क्लास से जब वो सीखना शुरू करता है तो उसकी पढ़ाई पर, उसके जीवन का स्तर और बेहतरीन हो जाता है। ये बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज में भी हुआ है। हमने विदेश में, हमारे अंबेडकर यूनिविर्सटीज में हमने इसमें स्टडी करवाई हैं और उसमें निकल के आयी है ये बात, बार–बार सामने कि दो साल से छः साल का बड़ा क्रिटिकल समय होता है बच्चे का। उसमें लर्निंग एबिलिटीज, अगर उसके अंदर डेवलप कर ली जायें इसलिए ये जरूरी था कि हम उस पर काम करें। इसे पॉयलट के रूप में इस साल से दस अर्ली चाईल्डहुड एजूकेशन सेंटर हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सौंपा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अर्ली चाईल्डहुड डिपार्टमेंट है एक। वो उसके लिए पूरी रिसर्च कैसे होगी, इसका फंक्शन कैसे होगा, इसके लिए चार करोड़ रूपये की राशि हमने इसको दी है और वो दस पायलट सेंटर शुरू करेगा और उसके बाद इससे लर्निंग के आधार पर दिल्ली में और सेंटर्स खोले जायेंगे। नर्सरी से ले के पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए क्लास में विशेष लाईब्रेरी बनाने की योजना है। ये भी एक बड़ा अंतर था। ये भी एक बड़ा अंतर था। सरकारी स्कूल के पहली क्लास के दूसरों क्लास के बच्चे और प्राईवेट स्कूल के पहली क्लास के, दूसरी क्लास के बच्चों के लिए बहुत अंतर ये दिखता था। उसका

अपना क्लासरूम रोता हुआ दिखता था। हम उनको डेकोरेट करा रहे हैं और हम बकायदा एक बहुत शानदार, बढ़िया, अच्छी किताबों की ताकि बच्चे वे किताब पढ़ सकें। पहलीं क्लास में नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक ये बच्चों के लिए क्लास में एक स्पेशल लाईब्रेरी, हर एक क्लास में बनायेंगे। ऐसी लाइब्रेरी पहली बार सरकारी स्कूलों में बनाई जाएगी। इससे बच्चों के लिए क हानियों की आकर्षक किताबें कक्षा में रखी जाएंगी। उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा, कुछ नया करने की भावना जगेगी और वह कहानी पढ़ने और सुनाने में दिलचस्पी लेंगे। इसके लिए 17 करोड़ रूपये की राशि अलग से इस बजट में रखा जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 400 नई लाइब्रेरीज, यह तो हुई नर्सरी से पांचवीं तक की। 400 नई लाइब्रेरीज छठी से 10वीं कक्षा के लिए बनाई जा रही है। इसमें बच्चों की उम्र और रूचि के हिसाब से रोमांचक कहानियां, कविताओं आदि की प्रसिद्ध पुस्तकें रखी जाएंगी ताकि बच्चों में पढ़ने की रूचि जागृत हो और लाइब्ररीज को बनाने और पुस्तकें लाने के लिए इस तरह की लाइब्रेरीज को बनाने के लिए 100 करोड़ रूपये की अनुमोदित प्रस्तावित राशि हम इस बजट में प्रस्तावित कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने 2017-18 में पांच स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना बनाई है। ये एक और नया कदम है। स्कूल आफ एक्सीलेंस, यह विद्यालय रोहिणी सेक्टर-17, मदनपुर खादर, फेज-2, खिचड़ीपुर, सैक्टर-22 द्वारका और कालकाजी में जो स्कूल की हमारी नई बिल्डिंग बनी है, उसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे पांच। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और प्री-स्कू में सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाएं चलेंगी हसमें। इनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं, प्रयोगशालाएं होंगी

ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल सकें। 2017-18 से 142 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर वाणिज्य स्तर की पढ़ाई हम शुरू करवा रहे हैं।

2017-18 में यूनिफार्म सब्सिडी को संशोधित किया जाएगा। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा। इसके लिए मैं 2017-18 के बजट में विद्यार्थियों के लिए सब्सिडी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, यूनिफार्म पर। नर्सरी से पांचवीं कक्षा के लिए यूनिफार्म के लिए 500 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये, छठी से आठवीं के लिए 700 रूपये से बढाकर 1400 रूपये ओर नवीं से बारहवीं के लिए 900 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

मीड डे मील, अध्यक्ष महोदय, पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए केंद्र की 100 परसेंट सपोर्ट से मीड डे मील स्कीम चलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि स्कूलों में बच्चों को दोपहर में दिए जाने वाले भोजन में वांछित स्तर की कैलोरी और गुणवत्ता युक्त पोषण सुनिश्चित करने में यह संभव नहीं है। ऐसा हमारे अध्ययन में है। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य के संसाधनों से हरेक विद्यार्थी को केला और उबला हुआ अंडा ऐडिशनल इसमें जोड़ने की योजना बनाई है। यह तो सिर्फ आठवीं तक के बच्चों के लिए होता है लेकिन जहां गर्ल्स स्कूल्स हैं, बालिका विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा की सभी छात्राओं को भी मधयाह्न भोजन की योजना के दायरे में लाकर इसका विस्तार किया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आएगी, वो तो है ही, राज्य सरकार की ओर से 55 करोड़ रूपये अतिरिक्त मैं प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी स्कूल की लैब्स में अधिकतम 11 कंप्यूटर होते हैं। अगले वित्त वर्ष में सभी लैब्स में 6 से 7 कंप्यूटर बढ़ाने का मैं

प्रस्ताव कर रहा हूं साथ ही दो शिफ्ट वाले स्कूलों में दो-दो कंप्यूटर लैब्स चलेंगी और 2000 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में कंप्यूटर लैब्स की संख्या बच्चों की संख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए मैं बजट में 182 करोड़ रूपये का अलग से प्रस्ताव करता हूं।

दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में कॉमर्स, स्ट्रीम, मैंने जिक्र किया, शुरू करेंगे। सभी स्कूल्स में पंजाबी और उर्दू के क्लब बनायेंगे, जिसमें बच्चों को पंजाबी और उर्दू, क्योंकि आम तौर पर होता है कि बच्चे के पास में लैंग्वेज के ऑप्शन तो कम हो हैं, बच्चा पढ़ता है तो एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है अपने साथ, लेकिन उसका मन होता है कि वो उर्दू भी समझ सके तो इसलिए जो पंजाबी और उर्दू के टीचर सरकार ने भर्ती किए हैं और कर रही है,उनसे हम पंजाबी और उर्दू के क्लब बनवायेंगे ताकि बच्चे रेग्युलर सब्जेक्ट के साथ-साथ उन क्लब्स में भी शामिल होकर उस भाषा की पोएट्री को समझ सकें। उसकी साहित्य में, उसकी कला में रूचि जग सके। इसी तरह सभी स्कूलों में आर्ट और म्यूजिक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अभी तक कहीं भी आर्ट और म्यूजिक की मेंडेटरी पढ़ाई नहीं है। साथ ही पहली बार हर स्कूल में एक डांस टीचर रखने की योजना भी बनाई गई है ताकि बच्चे परंपरागत, भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा ले सकें।

शिक्षकों के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं पिछले दो वर्षों में लागू की हैं जिसे उन्हें अपने काम को गरिमा से पूर्ण करने की मदद मिल सके। आगामी वर्ष में सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बने स्टाफ रूम्स को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करेंगे ताकि वहां शिक्षकों को बैठने के लिए अलग से वर्क्स स्टेशन मिल सकें। बैठने की अलग से जगह मिल सकें, उनके लिए चाय, कॉफी, पानी आदि की मशीनें भी वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस वर्ष सभी शिक्षकों को एक-एक कंप्यूटर टेबलेट, जो टेबलेट होता है, वो दिए जाने की योजना है ताकि सभी शिक्षक अपने छात्रों का डेटा या अन्य जानकारी इसमें रख सकें। इससे शिक्षकों का कागजी कार्रवाई पर व्यर्थ होने वाला समय काफी बचेगा। यह तो मैंने स्कूल की बात की।

थोड़ी हायर एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन की। अंबेडकर विश्वविद्यालय फिलहाल कश्मीरी गेट और कर्मपुरा स्थित अपने परिसरों से चल रहा है। कर्मपुरा में कॉलेज इसी साल शुरू किया है और 2100 विद्यार्थी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के चार नये परिसर 2022 तक खोले जाने हैं धीरपुर, रोहिणी, कराला और लोधी रोड में। इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2100 से बढ़कर 10000 हो जाएगी। लोधी रोड में अंबेडकर विश्वविद्यालय के तहत एक बेहद हाई क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जा रहा है। गुरू गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैम्पस का काम सूरजमल विहार में 271 करोड़ रूपये की लागत से जल्द शुरू हो जाएगा। यहां भी अध्यक्ष महोदय, हमें झेलना पड़ता है। ढाई साल पहले जब यहां राष्ट्रपति शासन था, ईस्ट दिल्ली सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन जैसे ही दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वहां डीडीए की तरफ से शर्त लगवा दी गई कि इस जमीन के लिए तो 16 करोड़ रूपये चाहिए। जो पहले से जमीन देकर जिस जिस चीज का उद्घाटन करवा दिया गया था, उस जमीन को देने के लिए बाद में शर्त लगा दी गई और दो साल से उसी में जूझती रही। अब इसको क्लीयर कराया है। यह ईस्ट दिल्ली कैम्पस भी जल्द शुरू हो जाएगा, इसके लिए 271 करोड़ रुपये की लागत से रोहिणी में 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज जून, 2017 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

अध्यक्ष जी, एनएसआईटी, डीटीयू, आईआईआईटी के विस्तार की परियोजनाओं पर हमने काम किया है पिछले 2 साल में। पूर्वी दिल्ली में अगले साल डीटीयू का नया कैम्पस शुरू हागा, जिसकी क्षमता 2000 विद्यार्थियों की होगी। इसी साल अगले सेशन से शुरू हो जाएगा। वर्तमान कैम्पस के विस्तार से 4 हजार और विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। इसी तरह एनएसआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 4000 से 10000 करने पर काम किया जा रहा है। आईआईआईटी दिल्ली का नया परिसर बनने से 1400 विद्यार्थी इसमें और दाखिला ले सकेंगे। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के नये परिसर की योजना बनाई गई है। इसकी क्षमता 3000 से बढ़कर सात हजार हो जाएगी।

भारत का पहला औषधि शिक्षा विद्यालय यानि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहला कॉलेज दिल्ली इंस्टीट्यूटऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ऐंड रिसर्च के रूप में दिल्ली में शुरू हो गया है। यह बार-बार पूछते हैं कि कॉलेज 20 का दावा किया था, कहां गये, 9 वोकेशनल कॉलेज हो गये, कर्मपुरा का कैम्पस हो गया, डीटीयू खोल रहे हैं। पहला औषधि विद्यालय कॉलेज हो गया। गिनते जाइये, अभी तो पांच साल होते-होते तो यह 20 का आंकड़ा पीछे छूट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और खेलों के लिए कोचिंग की सुविधाएं मजबूत करने के लिए, खेलों के बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रस्ताव है ताकि अच्छी खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएं। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो बहुमंजिला होस्टल बनाने की योजना बनाई है। इसमें 2350 खिलाड़ी रह सकेंगे। रह कर ट्रेनिंग ले सकेंगे। सरकार ने कैर गांव में खेल सुविधाएं विकसति करने का फैसला किया है। नजफगढ़ इलाके में समसपुर, खालसा और वसंतकुंज में शिक्षा विभाग

द्वारा हाल में अधिग्रहीत कथूरिया पब्लिक स्कूल में आवासीय खेलकूद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और खेल प्रशिक्षकों को 110 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे जो कि वर्तमान में केवल 19 हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बार-बार कहा है कि शिक्षा क्षेत्र हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और मैं वर्ष 2017-18 में शिक्षा पर कुल 11300 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 10186 करोड़ रूपये का राजस्व बजट और 1114 करोड़ रूपये की पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वचन के लिए 3525 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। दिल्ली के कुल बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कीरब 24 फीसदी का आबंटन देश के तमाम राज्यों में यह सबसे अधिक है और लगातार पिछले तीन साल से सबसे अधिक चल रहा है। इसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के हमारे संकल्प का पता चलता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य क्षेत्र में करना चाहता हूं। शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य भी दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार चाहती है कि दिल्ली का हर नागरिक अपने या किसी परिजन के बीमार होने की स्थिति में असुरक्षित महसूस न करें। उसके अंदर कोई डर न आये। उसके अंदर अस्पताल के बिल या सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कोई डर न आये, यह सरकार चाहती है। इसलिए पिछले दो साल में सरकार ने थ्री टियर हेल्थ सिस्टम स्थापित करने पर काम किया है। अगले वित्त वर्ष में भी यह सरकार इसी थ्री टियर सिस्टम को मजबूत करने पर काम करेगी।

फर्स्ट टियर यानी पहला स्तर है मोहल्ला क्लीनिक, जहां एक आम आदमी सामान्य बीमारी के लिए योग्य डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए जा सकता

है। इस मोहल्ला क्लीनिक में योग्य चिकित्सक की सेवाएं, दवाइयां, टेस्ट सब मुफ्त उपलब्ध कराये जाते हैं। 110 ऐसी मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक, इसी वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 150 से ऊपर हो जाएगी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे पता है विजेन्द्र गुप्ता जी का सवाल आएगा थोड़े दिन बाद सवाल आएगा ये एलजी साहब जिस दिन बोले तो 103 थीं वित्तीय बजट भाषण में 110 हो गई हो सकता है जिस दिन बजट प्रस्ताव पास हो रहा हो 120 हो जाएं तो ये डायनमिक कैसे आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसी तेजी से काम चल रहा है, रोजाना 2-3 कहीं कहीं हो रही हैं। इसी फाइनेन्शियल इयर के एंडत क आज मैं कह रहा हूं 110 काम कर रही हैं इसी फाइनेन्शियल इयर के एंड तक 150 काम करने लगेंगी, इसकी मुझे उम्मीद हैं। अगले वित्त वर्ष में हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स को पूरी दिल्ली में बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, इस पर तेजी से काम चल रहा है।

दूसरा स्तर है पॉलीक्लिनिक का, जहां हरेक बीमारी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे, दवाइयां और टेस्ट फ्री होंगे लेकिन यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता। ऐसे 23 पॉलीक्लिनिक शुरू कर दिये गये हैं और अगले वित्त वर्ष में इनकी संख्या डेढ़ सौ कर दी जाएगी। तीसरे स्तर पर अस्पताल है, जहां दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को मिलाकर 10,000 बेड्स हैं, आज की तारीख में इन्हें बढ़ाकर 20,000 बेड्स किये जाने पर इन्हीं अस्पतालों में काम चल रहा है, अगले 18 महीने में ये काम पूरा होने की उम्मीद है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बुराड़ी, अंबेडकर नगर, द्वारका में तीन अस्पताल निर्माणाधीन हैं और सरिता विहार, नांगलोई, मादीपुर और सिरसपुर में

चार अस्पताल बनाये जाने हैं। इन सात नये अस्पतालों में 5,000 नये बैड्स होंगे। इस तरह पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की संख्या आज के 10,000 से बढ़कर 25,000 के लक्ष्य पर अगले वित्त वर्ष में सरकार तेजी से काम करेगी। सरकार ने सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनवाने और उन्हें हेल्थ बीमा देने की योजना पर भी काम कर रही हैं, इन योजनाओं के लिए 20 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित कर रहा हूं। हमारी सरकार ने ऐसे मददगारों को सम्मानित करने का फैसला किया है जो सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने और उसके उपचार के लिए उसे अस्पताल में ले जाने में मदद करते हैं। ऐसे मददगार व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप 2,000 रूपये नकद का प्रशंसा पत्र दिया जाता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किशोरों के लिए पांच नशामुक्ति केंद्र स्थापित किये जाएंगे और प्रत्येक केंद्र में 5 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार के पांच अस्पतालों लोकनायक, गुरू तेग बहादुर, बाबा साहब अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों की फार्मेसियों का आउटसोर्स किया जाएगा और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के बाहर एक निशुल्क जन फार्मेसी, जन औषधि स्थापित की जा रही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन जांच पहले ही निशुल्क की जा चुकी है। सरकारी निजी भागीदारी के जरिए प्रयोगशाला सुविधाओं डायग्नोस्टिक टेली रेडियोलॉजी सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा और अगले वर्ष में इन सभी सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र के 41 अस्पतालों के साथ भागीदारी में 30 महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण उपचार की व्यवस्था करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है इसके अंतर्गत ऐसे रोगियों को

प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाएगा जिनका दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज चल रहा हो और जिन्हें अपेक्षित उपचार के लिए लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ रहा हो, इस तरह सरकारी अस्पतालों द्वारा रेफर किये गये चिंताजनक रोगियों के पूर्ण उपचार और देखभाल के लिए दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों को सीजीएचएस की दरों से उपचार का खर्चा आधा करेगी। 2017-18 के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मैं 5736 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित करता हूं, इसमें 5,048 करोड़ रूपये का राजस्व बजट और 688 करोड़ रूपये की पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2,627 करोड़ रूपये निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का तीसरा बड़ा इश्यू सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्तमान में डीटीसी और क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 5,815 बसें दिल्ली में परिचालित हैं जो हर रोज करीब 46 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती हैं। 2017-18 के दौरान क्लस्टर स्कीम के तहत 736 और नयी बसें शामिल हो रही हैं। बस डिपो टर्मिनल के लिए जगह के अभाव के कारण बसों के बेड़े में बढ़ोत्तरी करना एक बड़ी चुनौती थी, हमारी सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता दी और 11 नये बस डिपो बनाने का निर्णय लिया। ढ़िचाउकलां, द्वारका सेक्टर-22, बवाना सेकटर-1, बवाना सेक्टर-5, रेवला खानपुर, खड़खड़ी नाहर, रोहिणी फेज-5 में रानीखेड़ा-1, रानीखेड़ा-2 और रानीखेड़ा-3, नरेला और पूर्वी विनोद नगर में बनाये जा रहे हैं नय बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं मैं 2017-18 के दौरान बस टर्मिनल्स और डिपोज के विकास के लिए सौ करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। यात्रियों का अंतिम समय गंतव्य तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने 'letter of instance scheme' का अनुमोदन कर दिया है और फलस्वरूप

इस पर इस वर्ष 10,000 नये आटो परमिट जारी किये जाने की संभावना है। हमारी सरकार बसों के परिचालन में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए स्टेज केरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन शुरू की गई है। अब सभी क्लस्टर बसों में इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन लगाई गई हैं। डीटीसी की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन लगाने का इसमें प्रस्ताव है।

डीएमआरसी का मौजूदा नेटवर्क मैट्रो 189 किलोमीटर का है। डीएमआरसी के तीसरे चरण के पूरा होने पर यह लगभग 325 किलोमीटर हो जाएगा। सरकार ने मैट्रो के चौथे चरण का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 6 कारीडोर बनाये जाएंगे इनकी लंबाई 104 किलोमीटर होगी। चौथे चरण का काम 2017-18 में शुरू किया जाएगा और दिसंबर 2021 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मेट्रो यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए 582 अतिरिक्त डिब्बे भी खरीदने का प्रस्ताव है। मैं 2017-18 में डीएमआरसी के लिए 1,156 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करता हूं।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ रोड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद तक सभी ऐलीवेटेड कॉरीडोर्स को आम जनता के लिए अध्यक्ष महोदय, खोल दिया गया है इसमें आउटर रिंग रोड पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिली है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक नाले तक के एक तरफ समानांतर सड़क का निर्माण करने से भलस्वा, मुकुंदपुर, बुराड़ी, संगम विहार, जगतपुर, वजीराबाद अन्य निकटवर्ती कालोनियों के स्थानीय लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास के निर्माण का काम 2017-18 में शुरू कर लिया जाएगा। इस अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद नीला गुंबद, रोटरी से बदरपुर बार्डर की ओर आने वाले वाहनों को बिना किसी बाधा के निकलने में मदद मिलेगी और आश्रम चौक पर भीड़भाड़ कम की जा सकेगी।

अध्यक्ष जी, मैंने पिछले बजट में आईएसबीटी आनंद विहार से पीरागढ़ी तक ईस्ट-वेस्ट कारीडोर और वजीराबाद से एयरपोर्ट तक नॉर्थ-साउथ कारीडोर बनाने की घोषणा की थी, इन दोनों परियोजनाओं के लिए कंसलटेंट नियुक्त कर दिये गये हैं और फिजीबिलिटी स्टडी का काम इस पर प्रगति से चल रहा है। आईटीओ पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकंदरा रोड, मथुरा रोड, तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग, डब्ल्यू पाइंट और हंस भवन के निकट स्काईवॉक और एफओबी के निर्माण का प्रस्ताव है इस पर 54,84 करोड़ रूपये के खर्च का अनुमान है। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाला फेज-3 के अंतर्गत ऐलीवेटेड रोड का निर्माण कार्य इस साल पूरा हो जाएगा। मैं इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 150 करोड़ रूपये का प्रस्ता करता हूं। इसी तरह महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के बीच नये फ्लाई ओवर अंडरपास के निर्माण का काम भी 2017-18 में शुरू किया जाएगा। मैं 2017-18 में सड़क ढांचे सहित सार्वजनिक परिवहन के लिए कुल 5,506 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं इसमें 3,512 करोड़ रूपये राजस्व बजट और 1,994 करोड़ रूपये पूंजी का बजट शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बात अब सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। अध्यक्ष जी हम समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विधवा बेसहारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवा और बेसहारा महिलाओं के वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है करीब 6.3 लाख व्यक्तियों को ये लाभ दिया जा रहा है इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आवंटन 2017-18 में बढ़ाकर 1,595 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है जबकि 16-17 के संशोधित अनुमानों में ये 1,137 करोड़ रूपये था। हमारी

सरकार 2017-18 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना करेगी। यह कमीशन दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा संबंधी मसलों की देखरेख करेगा। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है इसमें स्टेशनरी खरीदने के लिए छात्रवृत्ति प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस आदि भी शामिल हैं। 2017-18 में एसएसटी कपोनेंट 789 बजट हैड के तहत 900 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं जो 16-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27 फीसदी अधिक है। 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए मैं कुल 3,467 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,081 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सामाजिक सुरक्षा की बात हो तो जिसका जिक्र आपने भी किया था, महिला सुरक्षा के बिना सामाजिक सुरक्षा संभवन नहीं है और और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली महिला आयोग ने पिछले दो वर्ष में इस तरह की निष्पक्षता के साथ काम करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी राज्य महिला आयोग ने इस तरह की निष्पक्षता और इस तरह की सक्रियता से काम करके दिखाया होगा। आज मैं बहुत अथोरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि दिल्ली महिला आयोग देश का एकमात्र ऐसा राज्य महिला आयोग है, जहां बैठी हुई महिला आयोग की अध्यक्षा किसी सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, इस सदन में 67 एमएलए सत्ताधारी पार्टी से है, सत्ताधारी पार्टी के किसी एमएलए या मिनिस्टर या उसके करीबी आदमी को भी नहीं बक्ख्शते। अगर वहां से भी कोई सूचना मिलती

है, अगर वहां से भी किसी को कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है, किसी तरह से शिकायत मिलती है, उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पिछले दो साल में जिस तरह से दिल्ली महिला आयोग ने काम किया है, उससे उसकी भूमिका समाज में और बढ़ जाती है और इसीलिये आपने अपेक्षा की थी, मुझे लगता है कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं वित्त मंत्री के रूप में, सदन के अध्यक्ष होने के नाते आपे सामने रख रहा हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। दिल्ली महिला आयोग का बजट पहली बार बढ़ाकर तीन गुणा किया गया है उसको बीस करोड़ रूपये की प्रस्तावित राशि दी जा रही है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, जनापूर्ति और स्वच्छता पर मैं बात करूंगा। पानी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है लेकिन रहीम जी जो कह गये हैं, उससे बढ़िया उस चीज को एक्सप्लेन कोई कर नहीं सका :

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी बिना ना ऊबरे मोती मानस चून।।

पानी की इससे ज्यादा इम्पोरटेंस जीवन में, अस्तित्व में क्या हो सकती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इतने सटीक और गहरे शब्दों में किसी ने कही होगी। हमारी सरकार इस बात का महत्व समझती है कि पानी मानव का अधिकार है, इंसान की बुनियादी जरूरत है पर ये कोई वस्तु नहीं हमारी सरकार का संकल्प है कि 2017 के अंत तक अधिकृत और अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले सभी परिवारों को पाइप लाईन के जरिये पेयजल प्रदान कर दिया जाये। दिल्ली जल बोर्ड 1200 अनाधिकृत कालोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान कर रहा है और सभी झुग्गी झोंपड़ियों में पब्लिक वॉटर हाइड्रेंटस के जरिये जलापूर्ति की जाती है और इस वर्ष दिल्ली की सभी जेजे क्लस्टर्स

में पानी की लाईन डालने का लक्ष्य रखा गया है। हम प्रत्येक परिवार को हर महीने बीस किलोमीटर नि:शुल्क जलापूर्ति करने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं गर्व के साथ सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि लगभग 12.57, बारह लाख सत्तावन हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं के जीरो वॉटर बिल आये हैं। यानि की बारह लाख सत्तावन हजार परिवारों ने जीरो वॉटर बिल स्कीम का फायदा लगातार उठाया है चाहे वह चिराग दिल्ली जैसे सैंकड़ों साल पुराने गांवों हों या किराडी की अनाधिकृत कालोनियों हों, दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पहली बार घर के अंदर पानी सप्लाई हुआ है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 12.57 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को जीरा वॉटर बिल देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रूपये का अतिरिक्त रेवेन्यू इकट्ठा करके दिखाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जल मंत्री और पूरी टीम है दिल्ली जल बोर्ड की, उसको बहुत-बहुत बधाई दी जानी चाहिए। ये नई इकॉनोमी है; आम आदमी को पानी पिलाओ, उसकी जीवन की जरूरतें पूरी करो, उसकी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत उसको मुफ्त में उपलब्ध कराओ सबको और इकोनोमिक्स में आपका ग्राफ इकोनोमिक कलक्शन में ऊपर उठता जा रहा है। ये नई इकोनोमी है, जिसको समझने की जरूरत है। दो हजार सत्रह-अट्ठारह का साल जल क्षेत्रों में दो मायने में महत्वपूर्ण है। एक ओर हम सभी अनाधिकृत कालोनियां और जेजे कलस्टर सहित समूची दिल्ली में पानी की पाईप लाईन बिछाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो वहीं वॉटर क्वालिटी को लेकर एक बड़ी शुरूआत हमने इस वर्ष की है, जिसको हम आगे बढ़ायेंगे। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाओं के मॉड्यूलाइजेशन की शुरूआत हमने पिछले साल शुरू की थी, उसको आगे भी जारी रखेंगे। पिछला साल वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐतिहासिक रहा। हमारी सरकार आने के बाद 309 अनाधिकृत कालोनियों ने पानी की सप्लाई शुरू की गई जो पूरे देश में एक मिसाल है।

वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 किलोमीटर लंबी पुरानी अवरूद्ध या क्षतिग्रस्त या रिसने वाली पाईप लाइन को हमने बदला। दिल्ली जल बोर्ड ने 700 टैंकरों के मौजूदा बेड़े में ढाई सौ नये स्टेनलेस स्टील के वॉटर टैंकर जोड़े हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर 29 वॉटर एटीएम और 15 ई-प्याऊ स्थापित किये गये हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कोरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी विधि से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में ई-प्याऊ गाने की और योजना बनाई है। दिल्ली जल बोर्ड शहर के विभिन्न भागों में चौबीस घंटे सातों दिन जलापूर्ति का सपना पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमेशा, हम इस सदन में भी बात करते रहे हैं। अलग-अलग दौर में बात होती रही है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम देश में आम आदमी को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो ये किस तरह की आजादी है, किस तरह की तरक्की पाई है, इस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली में भी हम और देश की राजधानी में नहीं करा पा रहे हैं तो और ज्यादा शर्मनाक बात है। हम बहुत तरक्की की बात करते हैं। बहुत विकास की बात करते हैं। हम आजादी की बात करते हैं लेकिन देश की राजधानी से हमने इसकी शुरूआत की है कि आदमी टोंटी खोल के अपना पानी पी सके, ऐसा सप्लाई पानी, गारेंटेड... कंटैम्नेशन वाला तो दिल्ली में भी पी रहे हैं, बहुत से लोग सप्लाई से पी रहे हैं कहीं आरओ लगा लेते हैं जो सक्षम हैं, लेकिन दिल्ली में हमने गारंटी ली है कि कालोनियों में अब आप अपना टोंटी खोलोगे तो पीने का जो साफ पानी आयेगा, वो गारंटेड होगा, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। नवजीवन बिहार और गीतांजलि इन्कलेव में इसकी शुरूआत कर दी गई है। इन इलाकों

में मार्च 2017 से 24 घंटे जलापूर्ति की जा रही है। इसके पहले इन क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पानी की आपूर्ति की जा रही थी। चौबीस घंटे और सातों दिन वॉटर सप्लाई से न केवल पानी की दिन रात उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि इस बात की गारंटी भी दी जा रही है कि टेप से सीधे स्वच्छ पेयजल मिले। टैप से सीधे पानी पीने की स्कीम इस वर्ष कुछ और कालोनियों में शुरू की जायेगी, जिसके बाद समूची दिल्ली में धीरे-धीरे इसमें विस्तार किये जाने की योजना है। 24X7 आपूर्ति सप्लाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। मौजूदा नेटवर्को को नया रूप दिया जा रहा है। 'वॉक द लाईन' नाम के नवीन कार्यक्रम के जरिये आपूर्ति प्रणाली का समूचे शहर में मूल्यांकन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से नेटवर्क की खामियों के बारे में व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पानी के लिये दिल्ली अन्य राज्यों पर निर्भर है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बरसात और बाढ़ का पानी रोक कर दिल्ली का वॉटर प्रोडक्शन बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास दिल्ली जल बोर्ड ने किया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वॉटर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम बुराड़ी में शुरू किया गया इसी के साथ दिल्ली जल बोर्ड ने पहली दफा शहर के भीतर पानी की मात्रा बढ़ाने के क्षेत्र में अपने प्रयास शुरू किये हैं। पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाते हुए कुल 20 एमजीडी जल का प्रोडक्शन बढ़ाया जायेगा, 92 नये ट्यूबवेल लगाने और पुराने 100 टयूबवेलों के पुनर्विकास, पल्ली में चार बरसाती कुओं और पुराने पंपों के साथपर नये पंप लगाने तथा एमसीएडीए की संस्थापना करने जैसे उपायों के जरिये जलापूर्ति में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार अवरूद्ध बरसाती कुओं को बहाल करने के लिए भी एक्शन प्लान बनाये जा रहाहै। इसी वर्ष कराला, मंगोलपुरी और मंगोलपुरी कलां में भूमिगत जलाशयों को चालू किया जा रहा

है और मायापुरी, महिपालपुर में यह काम शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष 309 कालोनियों में जलापूर्ति नेटवर्क कायम किया जाना दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में एक कीर्तिमान है। इससे सभी 1200 अनधिकृत कालोनियों में व्यापक जलापूर्ति कायम की जा सकी है ऐसी 200 और कालोनियों को जलापूर्ति नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना बनाई है। कोरोनेशन पिलर के निकट 70 एमजीडी क्षमता के सीवर वेस्ट प्लांट का निर्माण कार्य सितंबर, 2016 में शुरू किया गया। इसे 30 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। यह प्लांट आधुनिक तकनीक पर आधारित अपनी तरह का देश में सबसे कम लागत में बनने वाला प्लांट है। ये बार-बार पूछते हैं ना पैसा कहां से आता है? पैसा कहां से आता है? बेस्ट टैक्नोलॉजी, मिनिमन कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज दिल्ली गेट पर 15 एमजीडी सीवरेज उपचार संयंत्र और यमुना विहार में 25 एमजीडी उपचार संयंत्र एसटीपी चालू कर दिये गये हैं। सभी पुराने मल जल पम्पिंग स्टेशनों को स्वचालित बनाया जायेगा ताकि पम्पिंग का अनुकूलतम इस्तेमाल हो और टैंक सीवरों में चैनल फ्लों सुनिश्चित किया जा सके। इससे नालों की गाद हटाने के काम में कमी आयेगी। यमुना की सफाई के लिये तीन प्रमुख नालों नजफगढ़ सप्लीमेंटरी और शाहदरा ड्रेन पर इंटर सेप्टर सीवर बिछाने की परियोजना शीघ्र पूरी की जायेगी। इससे नालों में बहने वाले 240 एमजीडी मल जल का ट्रैप किया जायेगा और समुचित उपचार के लिये विभिन्न जल मल संयंत्रों की तरफ इसको मोड़ा जायेगा। सप्लीमेंटरी नालों को नया रूप देने के लिए कंसल्टेंसी का काम इजराइल की एक फर्म को दिया गया है। इस वर्ष मुकरबा चौक से वजीराबाद तक 8.5 किलोमीटर के दायरे में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर सप्लीमेंटरी ड्रेन की सफाई, अपलिफ्टिंग और विकास का काम शुरू किया जायेगा। मैं 2017-18 के लिये जलापूर्ति और स्वच्छता के लिये कुल 2108 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें 1108 करोड़ रूपये पूंजी बजट से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, आवास और शहरी विकास के बारे में दिल्ली सरकार के बारे में दिल्ली सरकार को स्लम फ्री शहर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, और कृतसंकल्प है लेकिन हमारी फिलोस्फी है कि ये काम झुग्गियों को उजाड़ कर नहीं हो सकता। सुबह 4.00 बजे वहां पुलिस भेजिए और रात को उनको तोड़ दीजिए। उससे नही हो सकता बल्कि झुग्गी में रह रहे नागरिकों को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए छोटे-छोटे घर देकर उसमें हो सकता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान डीयूएसआईबी ने ज्वालापुरी, कीर्त नगर, पंजाबी बाग, जनपथ, झारखंड भवन और एनएस-24 इत्यादि स्थानों पर बसी विभिन्न झुग्गी बस्तियों से करीब 5,000 व्यक्तियों को बापरौला और द्वारका में फ्लैट देकर पुनर्स्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, कई जगह मुझे जाने का अवसर मिला जहां झुग्गियों से फ्लैट में ले जा रहे थे लोग, लोगों की आंखों में ऐसे आंसू थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था और मुझे जिन शब्दों में बयां किया उन्होंने अपने उस भाव को, किसी ने मुझे बताया कि 3 बार उस झुग्गी को तोड़ा गया। हर बार सड़क पर खड़ा रोता रहा, रात को वहीं सोया फिर वापस जब पुलिस चली गई और बुलडोजर हट गए फिर वापस आकर झुग्गी बनाई, 3 बार ऐसा हुआ। किसी एक व्यक्ति की कहानी है ये। वो व्यक्ति कहता है कि आज मैं खुश हूं कि अबकी बार मेरा मकान तोड़ने के लिए कोई बुलडोजर नहीं आएगा, कोई चार बजे आकर पुलिस खड़ी नहीं हो जाएगी। ऐसे सैकड़ों लोगों को, 500 से ज्यादा लोगों को बापरौला और द्वारका में जो फ्लैट दिए गए हैं, कभी आप समय देंगे और इजाजत देंगे तो एक छोटा सा वीडियो हमने ऐसे लोगों का बनवाया है, मैं चाहूंगा कि वो सदन में कभी दिखाया जाए। कैसे लोग झुग्गियों में रह रहे थे और कैसे अब अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं और उनकी जिंदगी

में क्या बदलाव आया है, ये सदन देखकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेगा कि यहां से निकली, बनी नीतियों और बने कार्यक्रमों के जरिए लोगों की जिंदगी कहां से कहां पहुंच रही है, उस गौरवान्वित क्षण को महसूस करने के लिए मैं चाहूंगा कि किसी समय इस सत्र में या इससे अगले सत्र में वो वीडियो भी यहां पर दिखाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह दिल्ली को खुले शौच से मुक्त शहर बनाने पर, भी तेजी से काम शुरू किया गया है। मैं इसके लिए डीयूएसआईबी की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कई हफ्तों तक रोजाना सुबह तीन बजे जा-जाकर ऐसे इलाकों का सर्वे किया, जहां लोग खुले में शौच करते हैं। ये अद्भुत कार्य था क्योंकि आपको खुले शौच की स्थिति का जायजा लेना है, कहां-कहां हो रहा है तो सुबह उस वक्त जाना पड़ेगा जब खुले शौच के लिए लोग जाते हैं। तो डीयूएसआईबी डीयूएसआईबी की टीम सुबह तीन बजे उठ-उठकर घर से निकल-निकल कर वहां पर जाती थी, जहां-जहां से सूचनाएं मिलती थीं, जहां-जहां शिकायतें थी, जहां-जहां स्थितियां रिकार्ड में थी पहले से, वहां जाकर सर्वे करके, कई हफ्तों तक रोजाना सुबह जाकर सर्वे किया और इसके आधार पर दिल्ली को खुले शौच से मुक्त कराने का एक प्लॉन तैयार किया। इस प्लॉन पर काम करते हुए पूरी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ-सुथरे 8,000 टॉयलेट तैयार हो चुके हैं, 6,000 जून, 2017 तक तैयार हो जाएंगे। इस तरह कुल 19,000 टॉयलेट्स का निर्माण कर पूरी दिल्ली को खुले शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डीयूएसआईबी और नाइट शैल्टर की टीम की सक्रियता के कारण दिल्ली में हम ठंड के कारण

होने वाली मौत की घटनाओं को रोकने में कामयाब रहे हैं। डीयूएसआईबी दिल्ली में बेघर लोगों को शैल्टर प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 266 शैल्टर्स में कुल क्षमता बढ़ाकर 21,724 की गई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत नांगलोई फेज-2 द्वारका सैक्टर-3, रोहिणी सैक्टर-5, गीता कॉलोनी की निकटवर्ती जे. जे. बस्ती में बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाने का और प्रस्ताव है। प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कंबल, दरियां, चटाइयां, पेय जल आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

मैं 2017-18 में आवास और शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं के लिए 3,113 करोड़ रूपये के कुल व्यय का प्रस्ताव करता हूं जो कि संशोधित बजट 2016-17 से 21 फीसदी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा, दिल्ली सरकार ने सितंबर 2016 में सौर नीति को अधिसूचित करके सौर ऊर्जा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जगह की कमी की वजह से दिल्ली में सौर ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए इमारतों की छत का उपयोग करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 साल में सोलर फोटोवोल्टैक प्रणाली स्थापित करके 1,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने और 2025 तक इसे 2,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ऐसी सभी सरकारी इमारतों के लिए छतों पर सोलर एनर्जी प्रणालियां लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा का होगा। इन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर फोटोवोल्टैक पावर प्लांट लगाने पर 2/- रूपया प्रति यूनिट किलोवाट की दर से बिजली उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

शहरी ठोस कचरे के निपटारे की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन जगह ओखला, गाजीपुर और बवाना में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है जिनकी कुल क्षमता 52 मेगावाट होगी। ओखला में 16 मेगावाट क्षमता का संयंत्र पहले ही काम कर रहा है। यह भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन की ऐसी सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी क्षमता रोजाना 2,000 टन कूड़ा-करकट निपटाने की है।

मैं वर्ष 2017-18 में ऊर्जा पर कुल 2,194 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। जिसमें 1600 करोड़ रूपये बिजली सब्सिडी के शामिल हैं जिसकी वजह से आज दिल्ली के लाखों लोगों को बिजली के बिल आधे आ रहे हैं और लोगों ने बिजली की बचत भी शुरू की है और उसमें कुल मिलाकर 2,194 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी बात दिल्ली के पर्यावरण पर और वन क्षेत्र पर करना चाहूंगा। पर्यावरण की समस्या नगर और इसमें रहने वालों की खुशहाली से जुड़ी समस्या है। आबादी में बेतहाशा बढ़ोत्तरी और तेज आर्थिक विकास से दिल्ली में पर्यावरण के बिगड़ने की समस्या उत्पन्न हुई है। हाल ही में पर्यावरण के हालात सुधारने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनके अंतर्गत पेड़-पौधे लगाने, सभी वाणिज्यिक वाहनों में सीएनजी के उपयोग, बैटरी से चलने वाले चौपहिया व दुपहिया वाहनों पर सब्सिडी इस तरह के बहुत सारे उपाय दिल्ली सरकार ने किए हैं।

अध्यक्ष जी, हम प्रदूषण के स्तर की लगातार रीयल टाम आधार पर निगरानी कर रहे हैं जिसके लिए हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केंद्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें परिवेशीय वायु की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

इस तरह के केंद्रों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है जिनके माध्यम से वायु में विद्यमान धूल आदि के कणों और गैसों की मात्रा जैसे–पीएम 2, पीएम 10, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाईट्रोजन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है।

दिल्ली में प्रदूषण न फैलाने वाले बैटरी चलित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के बैटरी चलित वाहनों को अपनाने वालों को सब्सिडी देने की योजना पिछले साल घोषित की थी। वर्ष 2016-17 में 686 ऐसे वाहनों को 1.06 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गयी। यह सब्सिडी अगले साल भी जारी रहेगी।

अध्यक्ष जी, हम दिल्ली को हरी-भरी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2016 के दौरान हमने बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जिसके अंतर्गत पेड़ों के 8.43 लाख पेड़ और झाड़ीदार पेड़ों के साढ़े गयारह लाख पौधे रोपित किए गए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली के फोरेस्ट कवर में एक फीसदी का इजाफा हुआ है। ये एक फीसदी लगभग एक फीसदी है, 0.1 फीसदी है बेसिकली, ये बहुत छोटा लग सकता है लेकिन इसका मतलब है कि दिल्ली में करीब 600 एकड़ जमीन पर हरियाली और बढ़ गई है। 600 एकड़ बहुत बड़ा भू-भाग होता हैं

इसी तरह दिल्ली के पर्यावरण की दृष्टि से एक नया प्रस्ताव, मैं इस वर्ष सदन में रख रहा हूं जिसका संबंध दिल्ली में अंग्रेजों के उस समय के इतिहास से भी है। 1912-13 के आस पास अंग्रेजों ने दिल्ली में विलायती कीकर, पूरी दिल्ली में लगवाए थे। इसकी वजह से दिल्ली की जमीन के नीचे पानी की काफी समस्या बढ़ी है। सरकार की योजना है कि पूरी दिल्ली से विलायती

कीकर को हटाकर यहां अमलतास और स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएं और अन्य फल व फूलों के वृक्ष लगाए जाएं। पूरी दिल्ली को कीकर फ्री बनाने की इस योजना को इस साल सेंट्रल रिज इलाके से शुरू किया जा रहा है। बहुत बड़ी योजना है, पूरी दिल्ली में करना है। यह एक बहुत लंबी योजना है क्योंकि एकदम सारे कीकर काटकर नहीं फेंक सकते, धीरे-धीरे वहां और पौधे लगाकर, हल्के से उन कीकर को इस तरह से हटाया जाए ताकि वहां और कीकर ना उगे, उसके बाद बीच से वहां और कीकर ना बने, इसलिए मैंने कहा कि एक लंबी योजना है लेकिन इसकी हम शुरूआत इस साल से कररहे हैं और मुझे विभाग ने इसके लिए 10 साल पूरे बताए हैं कि लगभग 10 साल का इसमें पूरा समय लगेगा, पूरी दिल्ली को कीकर फ्री बनाया जा सकता है। इसवर्ष 2017-18 के लिए इस पर खर्च के लिएस 50 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित करता हूं।

रजोकरी में करीब 6 एकड़ में पहला वन्य प्राणी बचाव केंद्र (पक्षी विहार) बनाने का प्रस्ताव है जो विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। गढ़ी मांडू, बेला फार्म, शास्त्रीपार्क, इस्सापुर, खड़खड़ी जटमल, अलीपुर और मुखमेलपुर में नए नगर वनों के विकास का प्रस्ताव है ताकि यहां स्थानीय लोगों की पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2017-18 में पर्यावरण और वनों के लिए 106 करोड़ रूपये के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 75 करोड़ रूपये राजस्व के लिए और 31 करोड़ रूपये पूंजी बजट के लिए शामिल हैं। पर्यावरण और वन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए 57 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में गांव दिल्ली के सोशियो-इक्नोमिक-डायनैमिक्स का एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की बेहद कमी है। इसके लिए ''दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड'' लगातार विकास संबंधी कार्य करता रहा है। हमारा विचार है कि दिल्ली के शहरी गांवों में भी विकास कार्य उतने ही जरूरी हैं जितने दिल्ली के देहाती गांवों में। मुझे पता नहीं, कब वो योजना बनी थी कि दिल्ली के कुछ तो वाकई रूरल विलेजिज हैं लेकिन कुछ विलेजिज तो अर्बन और रूरल, सब एक जैसे ही है। मैं खुद जहां से विधायक हूं, पटपड़ गंज क्षेत्र से, मेरी विधान सभा में आने वाले तीन गांवों में से एक को रूरल विलेज डिक्लेयर कर रखा था। योजना में एक को अर्बन विलेज डिक्लेयर कर रखा था और एक किसी योजना में शामिल नहीं था। एक ही भू-भाग है, एक ही सोशियो-इक्नोमिक-डायनैमिक है वहां पर, तो वहां कैसे इसको बनाया था, इसको हम थोड़ा त्रुटि मानते हैं। इसलिए सरकार ने 'दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड' का दायरा बढ़ाकर रूरल और अर्बन, दोनों ही तरह के गांवों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए बोर्ड को दी जाने वाली राशि को वर्तमान में 132 करोड़ रूपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रूपये करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। यानि इसमें चार गुने से अधिक बढ़ोत्तरी की जा रही है। इस राशि का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सभी गांवों को उनकी आबादी के अनुपात में लगभग-लगभग 2-2 करोड़ रूपये की धनराशि का आबंटन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ लगने लगी है। इसमें भीड़-भाड़ कम करने के लिए हमने टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला किया है। इस पर 800 करोड़ रूपये लागत आएगी और इस परियोजना के दिसंबर 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

गाजीपुर में एक फूल मंडी है, हमने वहां पर 150 करोड़ रूपये की लागत से फूल मंडी और प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने का फैसला किया है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके। यह मंडी न सिर्फ फूलों के व्यापार केंद्र का कार्य करेगी बल्कि आम जनता भी यहां आकर फूलों की खूबसूरती का आनंद उठा सकेगी जिससे पुष्प उत्पादन और पर्यटन, दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, हम गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाजार का भी विकास करने की योजना बना रहे हें, जिस पर 120 करोड़ रूपये लागत आएगी। गाजीपुर के इस मछली-मुर्गा मार्केट में कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र भी लगाया जाएगा। यह परियोजना 2017-18 में ही पूरी हो जाएगी।

हमारी सरकार सभी मंडियों में ई-मंडी परियोजना लागू करने के लिए काम कर रही है ताकि लेन-देन में पारदर्शिता आए, उत्पादकों को बेहतर दाम मिलें और उन्हें अपने उत्पादों में भुगतान का कम समय लगे। हम राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई-पोर्टल में शामिल होकर चरणबद्ध तरीके से ई-मंडी परियोजना लागू करेंगे।

हमारी सरकार तमाम समुदायाओं की संस्कृति और धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता के क्रम में रहने समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2017-18 में दिल्ली में छठ घाटों के विकास के लिए 20 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में ग्रामीण विकास, बाढ़ एवं सिंचाई के लिये कुल 925 करोड़ रूपये के खर्च का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसमें 251 करोड़

रूपये का राजस्व बजट और 674 करोड़ का पूंजी बजट शामिल है। ग्रामीण विकास, बाढ़ एवं सिंचाई क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 704 करोड़ रूपये के खर्च का आवंटन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अपने बजट वक्तव्य के आखिरी चरण में मैं थोड़ी सी बात दिल्ली के पर्यटन और संस्कृति के बारे में भी करना चाहता हूं। दिल्ली देश के समृद्ध अतीत और फलते-फूलते वर्तमान का प्रतीक है। जहां प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। दिल्ली को पर्यटन नीति की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। दिल्ली को पर्यटकों के आकर्षण का विश्वस्तरीय केंद्र बनाने और दिल्ली पर्यटन के लिए ढांचागत एवं अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली को फिल्म शूटिंग के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक सिंगल विंडो मंजूरी व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है, शहर में फिल्म निर्माण और शूटिंग संबंधी कानूनी औपचारिकताएं केवल एक सरकारी कार्यालय में, सिंगल विंडो से पूरी हो सके ऑन लाइन पूरी हो सके, फिल्म निर्माताओं को मंजूरी प्रदान करने और उन्हें शूटिंग के नियमों के बारे में समेकित जानकारी प्रदान करने और फिल्म शूटिंग को एक बाधा-रहित अनुभव बनाने के लिए एक सुचारू प्रणाली हमारी सरकार विकसित करने जा रही है। हमने गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना के रूप में साफ्ट एडवेंचर पार्क डेवलप किया है जिसके चारों ओर आकर्षक हरित उद्यान फैला हुआ है जो एडवेंचर पार्क को एक जादुई परिवेश प्रदान करता है। गार्डन आफ फाइव सेंसेस में इस साल कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गईं। एक दिन में 15000 से ज्यादा फुट-फाल्स इस साल देखे गये। 2017-18 में गार्डन आफ

फाइव सेंसेस को नाईट लाईफ व लग्जरी फूड का हब बनाने का प्लान मैं प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष जी, दिल्ली को विश्वस्तरीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने का काम जारी रखते हुए हमने यमुना नदी के किनारों पर विकास की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य एक ऐसे स्थल का विकास करना है, जहां लोग अपने को प्रकृति और यमुना नदी से जुड़ा हुआ महसूस कर सके और नदी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और वे नदी में सुधार के लिये खुद भी प्रयास करें इससे जल निकायों के साथ-साथ ऐसी आद्र भूमि का विकास किया जा सकेगा जो भूमिगत जल पुनर्निर्माण और नदी के जलस्तर में सुधार लाने में सहायक हो। इससे नदी को प्रदूषण से बचाने और वन्य जीवों को सहारा देने वाले स्थानीय और वातावरण के अनुकूल पौध ों की विविध प्रजातियों के विकास में मदद मिलेगी। 5 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास ईकोलॉजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम में बनाने का प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017-18 में पर्यटन के लिए कुल 119 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 69 करोड़ रूपये का राजस्व बजट और 50 करोड़ रूपये का पूंजी बजट शामल है। पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 117 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली के विकास का, दिल्ली के सामाजिक ढांचे के विकास का लेखा-जोखा था। मैं थोड़ा सा समय सदन को इस बजट वक्तव्य का भाग 'ख' प्रस्तुत करने के लिए लेना चाहूंगा।

अपने भाषण के प्रथम भाग में मैंने सरकार की नीतियों की चर्चा की, मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार दिल्ली के आम जनों की, आम आदमी द्वारा बनाई गई है और आम आदमी के लिये है पिछले दो वर्ष से हम लगातार करमुक्त बजट, टैक्स फ्री बजट पेश करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष भी किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है और नहीं किसी कर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। दोस्तों, वैसे ये दिल्ली सरकार का लगातार तीसरा कर मुक्त, टैक्स फ्री बजट में पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का मालूम है कि जीएसटी का अनुमोदन हो चुका है और एक जुलाई से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है इसका असर सरकार के कर राजस्व पर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये राजस्व कर की वसूली 38 हजार 700 करोड़ रूपये का अनुमान है जो 16-17 के 32,430 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमानों से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। यह अनुमान इस विश्वास पर आधारित है कि जीएसटी लागू होने से कर में तेजी या उछाल आएगा और इन सब घटकों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव इसलिए मैंने नहीं रखा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2015-16 में ये टैक्स फ्री तो था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने पिछले दो बजट टैक्स रिवर्स भी किये हैं। बहुत सारे इशूज थे जिनको हमें व्यापारी आकर कहते थे क्योंकि ये सरकार एक तरफ मजदूरों की, एक तरफ कामगारों की व्यवस्था करती है, उनको रोजगार की, गरीबों की बात करती है तो जो व्यापारी जो रीढ़ की हड्डी होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की, उसकी भी सुविधा का ध्यान रखते हुए, उसकी भी सहूलियत का ध्यान रखते हुए आगे चलती है। लगातार पिछले दो बजटों में हमने चीजें टैक्स फ्री की हैं या टैक्स के स्लैबस को नीचे लाए थे और दिल्ली को सबसे लोएस्ट

वैट रेट के स्टेट को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। हमने 2015-16 में इमारती लकड़ी यानि टिम्बर पर टैक्स कम किया, दूसरे साल में भी कई चीजों पर टैक्स रेट घटाए। इस साल मैं कुछ और वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। सबसे इम्पार्टैंट महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिला सुरक्षा के लेके, महिला के सममान से लेके, महिला की जरूरत से लेके जुड़ा हुआ मुद्दा है। 20 रूपये तक के जो सैनेटरी नैपकिन्स थे, वो दिल्ली में अभी टैक्स फ्री थे। महिलाओं की स्वच्छता के प्रति सरकार के सरोकार को देखते हुए 20 रूपये से अधिक मूल्य वाले सैनेटरी नेपकिन्स के मामले में कर की मौजूदा दर 12.5 प्रतिशत है, इसको घटाकर मैं 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ-साथ दो साल पहले हमने टिम्बर पर टैक्स कम किया था लेकिन टिम्बर से जुड़े कुछ और पैरलल प्रोडक्टस है, लैमिनेटस, प्लाईवुड, ब्लैक बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड उन पर अभी 12.5 प्रतिशत का टैक्स है, इसको भी मैं घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बार टैक्स कम करने के क्रम में और बजट में इस वर्ष की इस सदन की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, क्योंकि हम दिल्ली में बैठके पूरे देश को देखते हैं और दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं है, सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि पूरे देश की राजधानी है, हम लोग यहां सदन में बैठ के उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पूरे देश से आकर अपने देश की राजधानी में रह रहे हैं। उनका जुड़ाव, उनी कनैक्टिविटी अपने शहर के लोगों से लगातार बनी रहती है। पूरे देश के छोटे-छोटे शहरों खासतौर पर नॉर्थ-ईस्ट के छोटे शहरों को देश की राजधानी से जोड़ने के लिए हवाई यात्राएं चलती है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के किसी छोटे शहर से जोरहाट से, दीमापुर, सेनापति जैसे किसी शहर से दिल्ली आना-जाना आसान हो सके, सस्ता हो सके, इस पूरे उत्तर

भारत के लोगों को दिल्ली बस पड़ोस का शहर लग सके और दिल्ली के लोगों को भी नॉर्थ-ईस्ट के शहर या बाकी और छोटे-छोटे शहर जहां से हवाई यात्राएं चल रही हैं, वो पड़ोस के शहर लग सके, इसमें हम दिल्ली के लोग भी अपनी तरफ से योगदान देना चाहते हैं और मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में यह बजट प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम यानि की आरसीएस जिसको कहा जाता है उसके अंतर्गत विमान परिचालन करने का जो विकल्प है, उसको स्कीम के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद भारत के भीतर दिल्ली सहित उड़ान के प्रारंभ स्थान और उतरने के स्थान, हवाई अड्डों, हैलीपेड से दो चुने हुए स्थानों के बीच जो रिमोटली कनैक्टेड सिटीज हैं, उनके मार्गों पर परिचालन करने वाले नगर विमान ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए एयर टरबाईन एटीएफ, एटीएफ की खरीद पर, अभी वैट की दर 25 प्रतिशत है जिसकी वजह से किराया बहुत महंगा होता है और छोटे-छोटे शहर और खासतौर से नॉर्थ-ईस्ट से मुझे बहुत महंगा होता है और छोटे-छोटे शहर और खासतौर से नॉर्थ-ईस्ट से मुझे बहुत लोग आ के मिले थे, वहां से दिल्ली आने के लिए उनको, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, छोटे-छोटे शहरों के लोग तो उसको टैक्स के रेट को हम 25 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैं समझता हूं ये दिल्ली देश की राजधानी की जनता की ओर से पूरे देश को विशेषकर पूर्वोत्तर के लोगों को, पूर्वोत्तर भारत के लोगों को संदेश है कि दिल्ली भी आपकी है, आपके लिए दिल्ली के दिल में बहुत जगह है।

तो अध्यक्ष महोदय, इस टैक्स रेट को 25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन इस बात से अवगत है कि हमारी सरकार व्यापारियों के अनुकूल सरकार है और पहले दिन से ही

हमारी ये कोशिश रही है कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए मददगार वातावरण बने। अतः एक विशेष अभियान हमने चलाया और मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 723 करोड़ रूपये व्यापारियों के रिफंड किये गये जो पिछले साल के 227 करोड़ रूपये की तुलना में 300 प्रतिशत एक्स्ट्रा है। कुल लिाकर 72 हजार रिफंड के मामलों का निपटारा किया गया। दिल्ली के व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी रिफंड उसको हमने ऐतिहासिक रूप से उसके सामने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं एक कहना चाहूंगा कि ये लगातार जो कुछ अभी तक मैंने कहा उसका अगर में समराईज करते हुए कहूं तो ये लगातार तीसरा जीरो टैक्स बजट है। ये न सिर्फ जीरो टैक्स है बल्कि लगातार हर साल हमने रिवर्स टैक्स का कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस समय रियल इस्टेट और कन्क्रीट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझने का दौर चल रहा है डेफिनेशंस में, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। कन्क्रीट में इन्वेस्टमेट करो तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हमने इंसान की जिंदगी में इन्वेट करना शुरू किया है। उसमें इन्वेस्ट करने का एक बजट पेश करना शुरू किया। लगातार तीसरा ये बजट लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट, इन सब जरूरतों को इन्वेस्ट करने के लिए किया है। दिल्ली को शिक्षित बनाना, स्वस्थ रखना, एक हमारा बड़ा सपना है और आज का ये बजट उस सपने की दिशा में मुझे एक मील का पत्थर साबित होते हुआ दिख रहा है। ऐसी मेरी उम्मीद है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में इन तमाम चीजों के बाद इन तमाम सपनों के बाद यही कहूंगा कि :

जिंदगी की उठान अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तेहान अभी बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने,
सारा आसमान अभी बाकी है।

अध्यक्ष जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के विचारार्थ इस बजट को प्रस्तुत करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि 2017-18 का बजट हाउस में पेश करें।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I present the Annual Budget fot the financial year 2017-18 before the house.[1]

वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि 017-18 की डिमांडस व ग्रांटस पेश करें।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I pesent the Demands for Grants for the financial year 2017-18.

वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि 2017-18 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांडस पेश करें।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I present Second and Final Batch of Supplementary Demands for the year 2016-17 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांडस पर डिमांड वाईज विचार करेगा :

---

[1]पुस्तकालय में संदर्भ सं. .....पर उपलब्ध।

डिमांड नं. 2 जिसमें रेवेन्यू में 27 करोड़ 05 लाख रूपये हैं, सदन के सामने है। :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

मैं दोबारा पढ़ रहा हूं।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

सप्लीमैंट्री डिमांड दो पास हुई।?

डिमांड नं. 3 जिसमें रेवेन्यू में 6 करोड़ 28 लाख रूपये और कैपिटल में 2 करोड़ रूपये है, कुल राशि 8 करोड़ 28 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 3 पास हुई।

डिमांड नं. 4 जिसमें रेवेन्यू में एक लाख रूपये और कैपिटल में 3 करोड़

86 लाख रूपये हैं कुल राशि 3 करोड़ 87 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 4 पास हुई।

डिमांड नं. 5 जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रूपये है सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 5 पास हुई।

डिमांड नं. 6 जिसमें रेवेन्यू में 34 लाख रूपये और कैपिटल में 2 करोड़ रूपये हैं, कुल राशि 36 लाख रूपये सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 6 पास हुई।

डिमांड नं. 7 जिसमें रेवेन्यू में 15 लाख रूपये और कैपिटल में 69 लाख रूपये है, कुल राशि 84 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 7 पास हुई।

डिमांड नं. 8 जिसमें रेवेन्यू में 1 करोड़ 30 लाख रूपये और कैपिटल में 194 करोड़ 57 लाख 6 हजार रूपये है, कुल राशि 195 करोड़ 87 लाख 6 हजार रूपये सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 8 पास हुई।

डिमांड नं. 9 जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपये और कैपिटल में एक लाख रूपये हैं, कुल राशि 2 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 9 पास हुई।

डिमांड नं. 10 जिसमें रेवेन्यू में 14 लाख रूपये और कैपिटल में 340 करोड़ 30 लाख रूपये है कुल राशि 449 करोड़ 58 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 10 पास हुई।

डिमांड नं. 11 जिसमें रेवेन्यू में 109 करोड़ 28 लाख रूपये और कैपिटल में 340 करोड़ 30 लाख रूपये है कुल राशि 449 करोड़ 58 लाख रूपये है, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमैंट्री डिमांड नं. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 144 करोड़ 58 लाख रूपये एवं केपिटल में 541 करोड़ 45 लाख 6 हजार रूपये, कुल राशि 686 करोड़ 3 लाख 6 हजार की सप्लीमेंट्री डिमांडस को मंजूरी दे दी है।

विनियोजन (सं. 1) विधेयक 2017 का पुरःस्थापन एवं पारण

अब माननीय उप मंत्री Appropriation No 1 Bill 2017 (Bill No 2017) को हाउस में इन्ट्रोड्यूसक रने की प्रमिशन मांगेंगे।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (N0.1) Bill; 2017 (Bill No. 01 of 2017) to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप-मंत्री जी काप्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation (No. 1) Bill, 2017 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व शेड्यूल, बिल का अंग बने :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड-2, खंड-3 व शेड्यूल, बिल का अंग बन गए।

प्रश्न है कि खंड–1 प्रीएम्बल और टाइटल बिल का अंग बने :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड–1, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए।

अब माननीय उप मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एप्रोप्रिएशन नं. 1 बिल 2017 को पास किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : Hon/ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriatio (No-1) Bill, 2017

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

एप्रोप्रिएशन नं. 1 2017 पास हुआ।

माननीय सदस्यगण, बजट प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में आज दोपहर का भोजन माननीय वित्त मंत्री जी के सौजन्य से विधान सभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

सदन की कार्यवाही दिनांक 09.03.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

विषय सूची

सत्र-5 भाग (1) बुधवार, 8 मार्च, 2017/17 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-47

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई	3-4
3	वार्षिक बजट 2017-18 का प्रस्तुतीकरण	5-61
4	वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं पारण :	61
5	वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं मतदान :	61-65
6	विनियोजन (सं. 1) विधेयक 2017 का पुर:स्थापन का पारण :	65-67